

हिन्दी, उर्दू, पंजाबी में एक साथ प्रकाशित दिल्ली सरकार की पत्रिका

अंक: फरवरी-मार्च 2018

दिल्ली

दिल्ली



आज़ादी के बाद दिल्ली की होली

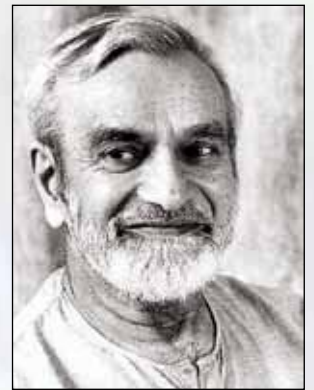
देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार राष्ट्रपति भवन में होली, दशहरा और दीवाली जैसे त्योहार सामूहिक रूप से मनाने की शुरुआत की। इस आयोजन में उनके मित्र, सेनाध्यक्ष और वहाँ के कर्मचारी आकर मिलते और अबीर—गुलाल का आदान—प्रदान होता। हिंदी नाटककार जगदीशचन्द्र माथुर ने इस बात की पुष्टि करते हुए अपनी पुस्तक “जिन्होंने जीना जाना” में लिखा है कि ‘होली पर राष्ट्रपति भवन में संगीत और रूपकों का आयोजन मुझे करना होता था। मुगल गार्डन में अतिथियों और औपचारिकता से घिरे राजेन्द्रबाबू को मैंने भोजपुरी में होली के लोक—संगीत पर झूमते देखा। वे लिखते हैं कि राष्ट्रपति भवन की दीवारें मानों गायब हो जातीं, दिल्ली का वैभव भी, उत्तरदायित्व का भार भी। सुदूर भारत के जिले के देहात की हवा मस्तानों को लिए आती और ग्रामीण हृदयों



का सम्राट अपनेपन को पाकर विभोर हो जाता।’

केवल राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के यहाँ भी साहित्यकार—संस्कृतिकर्मी जुटते थे। मशहूर रंगकर्मी जे. एन. कौशल ने अपनी आत्मपरक पुस्तक “दर्द आया दबे पांव” में लिखा है कि पंडित नेहरू के जन्मदिन और होली के अवसर पर प्रायः पंचानन पाठक (नेहरू के बाल सखा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पदस्थ) प्रधानमंत्री निवास पर जाया करते थे।

“दिल्ली” नामक उपन्यास के लेखक खुशवंत सिंह ने लिखा है— ‘मैंने तो होली पहली बार दिल्ली आकर मॉडर्न स्कूल में



दिल्ली

अंक : फरवरी-मार्च 2018

प्रधान सम्पादक

डॉ. जयदेव षडंगी

सम्पादक मंडल

संदीप मिश्र

डॉ. पंकज श्रीवास्तव

नलिन चौहान

कंचन आज़ाद

छाया चित्र

सुधीर कुमार, अजय कुमार, योगेश जोशी

“दिल्ली” पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं
में अभिव्यक्त विचार रचनाकारों के
अपने हैं तथा दिल्ली सरकार का इनसे
सहमत होना आवश्यक नहीं।

पत्राचार का पता

प्रधान सम्पादक

दिल्ली सूचना एवं प्रसार निदेशालय

दिल्ली सरकार

खंड सं. 9, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दूरभाष : 23819046, 23817926

फैक्स : 23814081

ई-मेल : delhidip@gmail.com



भगत सिंह के चार पत्र

21



इस अंक में...

हिन्दी

- दिल्ली के कोने-कोने पर पहुँचा विकास-केजरीवाल 2
दिल्ली को मिला 'ग्रीन बजट' का ऑक्सीजन! 7

पंजाबी

- ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 'ਗ੍ਰੀਨ ਬਜਟ' ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ! 1

उर्दू

- 1..... دہلی کو ملا گرین بجٹ کا آکسیجن





दिल्ली के कोने-कोने पर पहुँचा विकास-केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 14 फरवरी 2018 को सरकार की तीन साल की उपलब्धियों का ब्योरा पेश किया। प्रस्तुत है इस भाषण के मुख्य अंश—

यहाँ आए हुए सभी लोगों को और जो लोग इस कार्यक्रम को मीडिया के जरिए देख रहे हैं, सभी दिल्ली के लोगों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम।

पहले दिल्ली के लोगों को बहुत-बहुत बधाई। जनतंत्र के अंदर जनता मालिक होती है। नेता और अफसर, जनता के सेवक होते हैं। आज तीन साल पूरे हो रहे हैं। सरकार

के मुखिया होने के नाते जनता से रूबरू हूँ, हिसाब देने के लिए। मुख्य-मुख्य बातें आपके सामने रखूंगा।

पिछले तीन साल में काम बहुत सारे किए, लेकिन दो क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। वे हैं—शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना जबरदस्त निवेश कभी नहीं हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश-दुनिया के अनुभवों से सीखते हुए त्रिस्तरीय सिस्टम तैयार किया गया। सबसे नीचे दो कमरों वाला मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें ए.सी. लगा रहता है। 164 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं और 786 के लिए



जमीन तय हो चुकी है, काम शुरू होने जा रहा है। यानी कुछ महीनो बाद 950 मोहल्ला क्लीनिक बन जाएंगे। दिल्ली का क्षेत्रफल 1,484 वर्ग कि.मी है। इस तरह से हर एक-डेढ़ कि.मी पर दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक होगा जहाँ सबके लिए सारी दवाएँ, 212 टेस्ट, सारा इलाज फ्री हैं, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों।

लेकिन मोहल्ला क्लीनिक में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होते। दिल्ली में 26 पॉलीक्लीनिक खुल चुके हैं, 94 के लिए जमीन तय है और पैसा सेंक्शन हो चुका है। जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। यानी कुछ ही महीनों में दिल्ली में 120 पॉलीक्लीनिक बन जाएंगे। वहाँ 8 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मशीनें होंगी। लेकिन अगर बीमारी ज्यादा बड़ी है तो फिर सुपर स्पेशिएलिटी हास्पिटल जाना होगा। पॉलीक्लीनिक में मरीज को भर्ती करने की सुविधा नहीं होगी।

सुपर स्पेशिएलिटी अस्पतालों में बड़ा विस्तार हो रहा है। सत्तर साल में 10 हजार बेड की क्षमता हुई है दिल्ली में, जिसे बढ़ाने का काम जारी है। अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक 3000 नए बेड की व्यवस्था हो जाएगी। उसके अगले साल 2500 बेड और बन जाएंगे। इस तरह नए 5500 बेड बन जाएंगे। यानी चार साल में 50 फीसदी से ज्यादा इजाफा हो जाएगा।



दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में दवाएँ, टेस्ट, इलाज फ्री है। भारत में यह पहली बार हो रहा है। दिल्ली के हर बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है।

लेकिन यह देखते हुए कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भीड़ बहुत ज्यादा है, एमआरआई की लाइन लंबी है, दिल्ली सरकार ने एक टैंपेरी व्यवस्था की है। अगर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में तुरंत टेस्ट की सुविधा नहीं मिल रही है तो 133 किस्म के टेस्ट, 67 लैब्स और अस्पतालों में कराइए, जो इनपैनल हैं। इसका पैसा सरकार देगी।



सरकारी अस्पताल अगर एक महीने के अंदर ऑपरेशन की तारीख नहीं देते तो इनपैनल 44 निजी अस्पतालों में ऑपरेशन कराइए, सरकार पूरा पैसा देगी। इन सब कारणों की वजह से और जो बड़े स्तर पर निवेश हुआ, उससे ओपीडी तीन साल में तीन करोड़ से बढ़कर चार करोड़ हो गई है। पहले लोग सरकारी अस्पताल में जाना नहीं चाहते थे। लेकिन आज ओपीडी आने वाले मरीजों की तादाद में यह 33 फीसदी इजाफा उन्हीं डाक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की वजह से हुआ।

मैंने कई अस्पतालों में औचक दौरा किया। लाइनों में लोगों से पूछा तो 90-95 फीसदी लोगों ने कहा कि दवाएँ मिल रही हैं। बस शिकायत है कि लाइन लंबी हो गई है। इसे दुरुस्त करने के प्लान बना रहे हैं।

सरकार के 3 साल

एक और नीति नई बनी है। अभी तक एक्सीडेंट होता था तो आम आदमी घायल को अस्पताल पहुँचाने में हिचकता था, क्योंकि लगता था कि पुलिस का झंझट होगा और पैसा भी खर्च करना

पड़ेगा। तो दूसरी समस्या का समाधान निकाला है कि दुर्घटना से जुड़े इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। दुर्घटना के बाद शुरुआती एक घंटा, मेडिकल टर्म में गोल्डन आवर कहा जाता है, अगर इस एक घंटे में इलाज मिल जाए तो जान बच सकती है। तो अब बगैर चिंता के पास के सबसे बेहतर अस्पताल में घायल को बेहिचक पहुँचाइए। खर्च की चिंता किए बगैर।

भारत सरकार के कुल बजट का स्वास्थ्य पर खर्च ढाई प्रतिशत है, हरियाणा में साढ़े चार प्रतिशत, राजस्थान में सवा तीन प्रतिशत, यूपी में साढ़े तीन प्रतिशत और दिल्ली में 12 फीसदी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के नागरिक स्वस्थ रहें।



कभी हर घर से पानी बिजली के बिल की शिकायत रहती थी कि बहुत बिल आ रहा है, भरा नहीं जा रहा है। इस सरकार ने पानी-बिजली में राहत दी है। पहले हर साल बिजली का बिल बढ़ता था। तीन साल में बिजली का बिल बढ़ने नहीं दिया हमारी सरकार ने। उल्टा बिजली के बिल आधे कर दिए।

उदाहरण से समझिए। अगर आप 400 यूनिट इस्तेमाल अपने घर में करते हैं तो 2010 में बिल आता था 1340 रुपये। हर साल रेट बढ़ते थे। 2014 में बढ़कर हुआ 2040 रुपये। लेकिन आज 2018 में 1170 रुपये बिल आता है।



देश में महंगाई तो देखी थी, पहली बार सस्ताई देख रहे हैं।

दूसरे राज्यों से तुलना करें। चार सौ यूनिट बिजली के लिए दिल्ली में बिल आता है 1170 रुपये, यूपी में 2665 रुपये, मध्यप्रदेश में 3357 रुपये, महाराष्ट्र में 3160 रुपये और राजस्थान में 2697 रुपये।

देश में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली में है। 24 घंटे बिजली मिल रही है। पावर कट में जबरदस्त कमी आई है। पिछले साल पीक ऑवर में 6500 मेगावाट बिजली की ऐतिहासिक माँग पूरी की गई। हमने 582 नए ट्रांसफार्मर लगाए जिससे पावर कट बंद हो गए। जिस साल हमारी सरकार बनी थी, 2014-15 में, उस साल साढ़े 11 करोड़ यूनिट बिजली कटौती हुई थी, पिछले साल डेढ़ करोड़ यूनिट कटौती हुई, न के बराबर। कुछ जगह लोकल प्रॉब्लम हैं, बाकी पूरी दिल्ली में बिजली की कटौती बंद हो गई है।



पिछले तीन साल में 11 फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। सरकारी स्कूलों में तीन साल में 7030 क्लासरूम बनाए हैं, 8000 क्लासरूम बन रहे हैं और इस साल



बनकर तैयार हो जाएंगे। यानी चार साल में लगभग 15000 क्लासरूम. बन जाएंगे। 300-350 क्लासरूम एक नए स्कूल के बराबर हैं। पिछले तीन साल में 20 शानदार नए स्कूल बनकर तैयार हो गए हैं, 28 बन रहे हैं जो एक साल में तैयार हो जाएंगे। यानी चार साल में 48 नए स्कूल बन जाएंगे।

हमने तीन साल में 16000 सामुदायिक शौचालय बनाए हैं जिनका महत्व झुग्गी में रहने वाले, खासतौर पर महिलाएं समझती हैं। रैन बसेरे में बेघर लोग रहते हैं, पहले 175 थे अब 265 रैन बसेरे हैं। यानी 90 नए रैन बसेरे बने हैं।



हमने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त किया। पानी की बिल में बड़ी सहुलत मिली। पिछले तीन साल में 448 नई कालोनियों में पानी की पाइपलाइन पहुँचीं। 69 नई कालोनियों में काम चालू है। अगले साल-डेढ़ साल में हर घर में टोटी से पानी आएगा, टैंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बीते तीन साल में 46 नई कालोनियों में सीवर की पाइप लाइन डाल दी गई है। तीन साल में 337 कालोनियों

में काम चल रहा है जो इस साल पूरा हो जाएगा। यानी इस साल के अंत तक 383 में कॉलोनियों में सीवर।

जब हमारी सरकार बनी थी तो पानी का उत्पादन 800 मिलियन गैलन प्रति दिन था, यह आज 920 मिलियन गैलन हो गया है। 2000 नई बसें इस साल खरीदेंगे जिसमें एक हजार डीटीसी और एक हजार क्लस्टर की होंगी। 500 ई बसें खरादने का इरादा है, कॉमन मोबिलिटी कार्ड शुरू हो चुका है। ई रिक्शा को



बढ़ावा दे रहे हैं। हर रिक्शे की खरीद पर 30 हजार की सब्सिडी दे रहे हैं।

न्यूनतम मजदूरी सबसे ज्यादा दिल्ली में बढ़ी है। ऐतिहासिक इजाफा हुआ है। किसी और राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि न्यूनतम मजदूरी साढ़े नौ हजार से सीधे साढ़े 13 हजार कर दी गई। 35-40 फीसदी इजाफा। 'जॉब मेला' का कान्सेप्ट शुरू किया गया है। अब तक 6 जॉब फेयर आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें 268 कंपनियां आई और 24385 लोगों को शार्टलिस्ट किया गया। बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन जिन्हें एक हजार मिलती थी, उनकी दो हजार और जिन्हें डेढ़ हजार मिलती थी उन्हें ढाई



हजार कर दी गई। एक लाख नई पेंशन शुरू की गई हैं।

दलित छात्रों के लिए जयभीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है। एस.

सी और एसटी के तमाम बच्चे 12वीं के बाद कोचिंग नहीं ले पाते थे। मेडिकल और इंजीनियरिंग की या ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज, बैंकिंग या दूसरी नौकरियों की, अब उनकी कोचिंग का पैसा दिल्ली सरकार देगी ताकि इन्हें अच्छी कोचिंग मिल सके।

प्रदूषण बढ़ा मुद्दा है। ऑड-ईवन बड़ा मुश्किल कदम था। दिल्ली वालों ने बढ़-चढ़कर इसमें भाग लिया और



सफल बनाया। लेकिन इसे नियमित नहीं कर सकते। हमने राजघाट और बदरपुर प्लांट्स को बंद कर दिया। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जुर्माना पचास हजार से पांच लाख किया, लेकिन इन सब कदमों से ज्यादा असर नहीं पड़ा। पर्यावरण को लेकर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ प्रस्ताव हैं इस साल जैसे बड़े पैमाने पर लैंड स्केपिंग करना। सौ फिट से ज्यादा चौड़ी जो सड़कें हैं, उनके दोनों ओर घास उगाई जाएगी और पेड़ लगाएँगे ताकि मिट्टी न उड़े। इससे खूबसूरती बढ़ेगी। ऐसी सड़कों की लंबाई 500 किमी है। 2000 बसें आ रही हैं और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अभी कोई स्टडी नहीं है जो ठीक-ठीक बता सके कि क्या कारण है प्रदूषण का। हमेशा कारण बदलते रहते हैं। सरकार एक व्यापक अध्ययन कराएगी। ऐसी मशीन लगाई जाएगी जिससे तुरंत पता चलेगा कि इस समय किस कारण प्रदूषण है।

अभी यूपी से हरियाणा जाना होता है तो पूरी दिल्ली क्रास करते हैं। इससे निजात मिल जाएगी। जून तक दिल्ली के चारो तरफ सड़क बन जाएगी जिसमें यह भी तय

किया जा रहा है कि जो भी एजेंसी सड़क काटेगी, वही रिपेयर भी करेगी। ठेकेदार को पेमेंट तभी होगा। इससे भी प्रदूषण बढ़ता है।

आने वाले साल के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश जारी रहेगा और साथ में गलियों और सड़कों को बेहतर बनाने का अभियान चलेगा। सीसीटीवी का काम जल्द शुरू हो जाएगा। टेंडर हो गया है। गवर्नंस में क्रांतिकारी काम शुरू हो रहा है — घर पर सेवा। अभी कोई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है। तीन-तीन, चार-चार बार जाना पड़ता है। दलाल भी होते हैं। अब एक नंबर देंगे, उस पर फोन करिए। आप अपनी सुविधा का समय बताइएगा। कर्मचारी आपके घर जाएगा बायोमैट्रिक मशीन लेकर। सारे कागज तैयार रखिएगा और सर्टिफिकेट आपके घर डाक से पहुँच जाएगा। यह राशन में भी होगा। जितना बनता है, उतना राशन बोरी में पैक करके घर भेज दिया जाएगा।

फ्री वाईफाई की योजना इस साल इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। पार्क की रखरखाव के लिए आरडब्ल्यू को साथ ले रहे हैं। जो रहते हैं वही रखरखाव करने में रुचि लेते



हैं। पहली बार दिल्ली के कोने-कोने में विकास दिख रहा है। पानी, सीवर और नाली हर कालोनी तक, विकास कोने-कोने तक जा रहा है। हमारा विजन है कि दिल्ली एक माडर्न, वाइब्रेंट, पोल्यूशनफ्री और स्मार्ट सिटी के रूप में जानी जाए।

सवाल ये उठता है कि पैसा कहां से आ रहा है। सीवीसी ने संसद की रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार में 81 फीसदी की कमी आई है। पैसा बच रहा है और विकास के काम आ रहा है।

वित्तमंत्री ने पेश किया 53000 करोड़ रुपये का बजट दिल्ली को मिला 'ग्रीन बजट' का ऑक्सीजन !

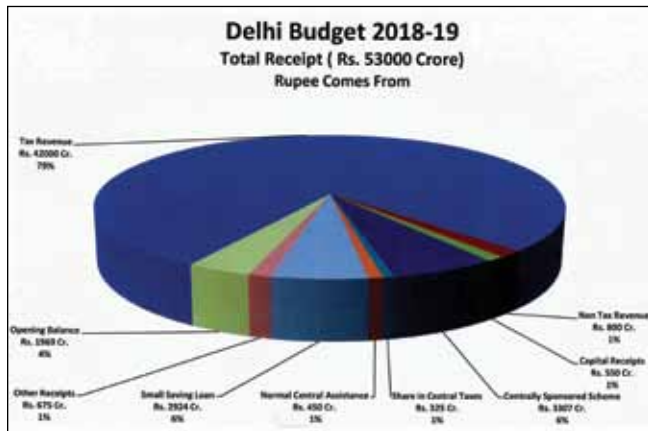
23 मार्च को विधानसभा में 2018-19 का बजट पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि देश में संभवतः पहली बार कहीं ग्रीन बजट पेश किया जा रहा है कुल 53000 के इस बजट में, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनहित की तमाम योजनाओं के अलावा देश की राजधानी को प्रदूषणमुक्त करने पर खास जोर दिया गया है। ग्रीन बजट में दिल्ली सरकार के चार विभागों पर्यावरण, ट्रांसपोर्ट, पावर और पीडब्ल्यूडी से जुड़ी 26 योजनाओं को शामिल किया गया है जिनके जरिए प्रदूषण नियंत्रण अभियान को नई ऊँचाई देने की योजना है।

बजट पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार ने 'ट्रिकल-डाउन' की जगह 'ट्रिकल-अप-इकोनॉमिक मॉडल' को अपनाया है। 'ट्रिकल-अप-इकोनॉमी' का सीधा सा मतलब है कि सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां बनाये जिनका सीधा लाभ गरीब और मिडल क्लास नागरिकों को मिले और उनकी शिक्षा का स्तर बढ़े, वे स्वस्थ रहें और उनकी आय भी बढ़े। यही इस सरकार का एकमात्र नारा है—'शिक्षित राष्ट्र, स्वस्थ राष्ट्र, समर्थ राष्ट्र'।

DELHI BUDGET 2018

श्री सिसोदिया ने कहा कि तीन साल पहले उनकी सरकार ने अपने पहले बजट में शिक्षा का बजट

लगभग दोगुना और स्वास्थ्य का बजट डेढ़ गुना किया था। पिछले तीन साल से लगातार सलाना बजट का करीब एक चौथाई हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है जो ना सिर्फ देश में सबसे ज्यादा है बल्कि सारे राज्यों के औसत शिक्षा खर्च – 15.6 प्रतिशत से कहीं अधिक है। इसी तरह आम आदमी को बेहतरीन मौहल्ला क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक और जन उपयोगी स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दिल्ली के आम परिवार की मेहनत की कमाई मोटे-मोटे मेडिकल बिल्स पर न खर्च हो। पिछले 3 साल में दिल्ली सरकार स्वास्थ्य पर अपने सलाना बजट का 11.3 प्रतिशत खर्च कर रही है जबकि सारे राज्यों का कुल औसत 4.9 प्रतिशत तक सीमित है।

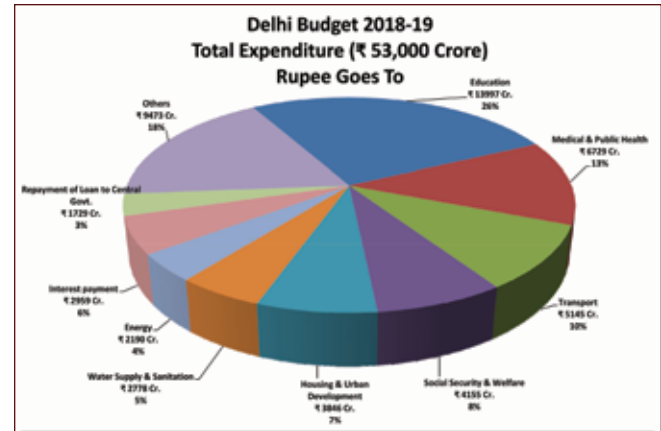


उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से दिल्ली के नागरिकों को देश के किसी भी बड़े शहर की तुलना में सस्ती बिजली मिल रही है। इसी तरह निःशुल्क पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की योजना से न सिर्फ दिल्ली के नागरिकों को सीधे आर्थिक फायदा पहुँचा है बल्कि 20 किलो लीटर की मासिक सीमा होने के कारण लोगों में पानी बचाने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है और बड़ी संख्या में लोगों ने पानी के वैध कनेक्शन लिये हैं। इन योजनाओं की बदौलत सरकार ने 400 नई कालोनियों में घर-घर में पीने के पानी का कनेक्शन पहुँचाया है। ट्रिकल-अप-इकोनोमी की दिशा सरकार का सबसे बड़ा कदम रहा है— न्यूनतम मजदूरी की सीमा बढ़ाना। पिछले साल ही दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। देश में आज सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी दिल्ली में मिलती है।

आर्थिक परिदृश्य

श्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था स्थायी विकास के सही मार्ग पर आगे बढ़ रही है। दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर, अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2017–18 में बढ़ कर 6,86,017 करोड़ रुपये पर पहुँच जाने की संभावना है, जो 2016–17 में 6,16,826 करोड़ रुपये था। इस तरह इसमें 11.22 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। स्थिर मूल्यों पर वास्तविक संदर्भ में दिल्ली के जीएसडीपी की वृद्धि दर 2017–18 में 8.14 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 6.6 प्रतिशत है। दिल्ली के जीएसडीपी में वास्तविक वार्षिक औसत बढ़ोतरी 2015–16 से 2017–18 की अवधि में 9.1 प्रतिशत रही है, जबकि इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी में बढ़ोतरी 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान 2011–12 के 3.94 प्रतिशत से बढ़कर 2017–18 में 4.10



प्रतिशत हो गया। यह उपलब्धि इसके बावजूद प्राप्त हुई है कि देश की कुल आबादी में दिल्ली की हिस्सेदारी केवल 1.4 प्रतिशत है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की प्रमुखता है, जिसकी हिस्सेदारी ग़ोस-स्टेट-वैल्यू-एडिशन में 85.92 प्रतिशत है। इसके बाद 12.04 प्रतिशत योगदान माध्यमिक क्षेत्र का और 2.04 प्रतिशत योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय वर्तमान मूल्यों पर 2017–18 में बढ़ कर 3,29,093 रुपये हो गई, जो 2016–17 में 3,00,793 रुपये थी। इस तरह 2017–18 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय में 9.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो एक अच्छा संकेत है। राष्ट्रीय औसत से तुलना करें तो दिल्ली की प्रति व्यक्ति

आय 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय स्तर की 1,12,764 रुपये की औसत प्रति व्यक्ति आय से करीब 2.92 गुना अधिक है।

ग्रीन बजट

वित्तमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पहला बजट पेश किया था तो उसे शिक्षा-स्वास्थ्य बजट का नाम दिया गया था। पिछले वर्ष पेश बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ बजट-आउटकम्स यानी जनता के टैक्स के पैसे को खर्च करके उससे मिलने वाले आउटकम पर जोर देते हुए उसे आउटकम बजट कहा गया। इस वर्ष बजट में ग्रीन बजट के नाम से एक और महत्वपूर्ण अंग जोड़ा जा रहा है।

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने सस्टेनेबल डेवलेपमेंट पर काम कर रहे ग्लोबल-थिंक-टैंक 'वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट' के साथ सहभागिता करके यह समझने की कोशिश भी की है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए दिल्ली सरकार के ग्रीन बजट प्रस्तावों का दिल्ली में प्रदूषण पर क्या असर पड़ेगा। इससे दिल्ली में प्रदूषण उत्सर्जन में काफी कमी देखने को मिलेगी।

श्री सिसोदिया के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहाँ प्रदूषणकारी तत्वों का रियल-टाईम-डेटा पूरे साल इकट्ठा किया जायेगा। और उनके कारणों का निरंतर अध्ययन किया जायेगा। यह कार्य वाशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसी के साथ-साथ पूरी दिल्ली में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की फेहरिस्त बनाने का काम भी पहली बार शुरू होगा। यह कार्य विश्व के सबसे बड़े शहरों के समूह सी-40 सिटीज-फॉर-क्लाईमेट-लीडरशिप के साथ मिलकर शुरू किया जायेगा।

ग्रीन बजट से संबंधित विभागवार योजनाएँ

पर्यावरण विभाग

दिल्ली में अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने की दिशा में सरकार पिछले 3 साल से मिशन-मोड में काम कर रही है। इस साल दिसंबर 2017 तक 5.5 लाख पौधे पहले ही लगाए जा चुके थे। मार्च 2018 तक तीन लाख और पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा डिवाइडर और सड़क के किनारों पर सिविल एजेंसियों द्वारा 7.93 लाख छोटे पेड़-पौधे

लगाये गये। नागरिकों को 3.5 लाख पौधे निःशुल्क वितरित किए गए ताकि वे अपने घरों के आगे

पीछे आंगनो में उन्हें लगा सकें। इन प्रयासों से अच्छे परिणाम सामने आए और दिल्ली का हरित क्षेत्र 2015 में 299.77 वर्ग किलोमीटर से बढ़ कर 2017 में 305.41 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अगले साल सरकार आरडब्ल्यूए मार्किट एसोसिएशन और एनजीओ के साथ मिल कर बड़े पैमाने पर दिल्ली में लाखों और पौधे लगाने की तैयारी में है। इसके लिए एयर-एबियंस-फंड का इस्तेमाल किया जायेगा। सेंट्रल रिज एरिया में विलायती कीकर के स्थान पर नए पौधे लगाने की एक दीर्घावधि योजना शुरू कर दी गई है।

दिल्ली को हरा-भरा बनाये रखने के अलावा प्रदूषण से लड़ने के लिए कई नई प्रोत्साहन योजनाएँ भी सरकार ने तैयार की हैं। सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्रदूषणकारी ईंधन इस्तेमाल करने की जगह पाईपड नेचुरल गैस के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए 1 लाख रुपये तक की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जायेगी। इसी तरह दिल्ली के रेस्टोरेंट्स को भी कोयला तंदूर की जगह इलेक्ट्रिक या गैस तंदूर के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए 5 हजार रुपये प्रति तंदूर तक की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जायेगी। साथ ही 10 केवीए या इससे अधिक क्षमता के डीजल जनरेटर इस्तेमाल करने वाले व्यवसायियों को भी स्वच्छ ईंधन पर आधारित इलेक्ट्रिक जनरेटर इस्तेमाल



करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसके लिए 30 हजार रुपये तक की सहायता राशि सरकार

की ओर से दी जायेगी।

दिल्ली के नागरिकों को प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सहभागी बनाने और इसके खतरे के प्रति, हर पल सतर्क बनाने के उद्देश्य से पब्लिक डीलिंग वाले सरकारी कार्यालयों में वायु प्रदूषण के लेवल की जानकारी देने वाले करीब एक हजार इंडोर डिस्पले पैनल लगाये जायेंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति के पूर्वानुमान के लिए वर्ल्ड बैंक की टीम के परामर्श से एक मॉडल डेवलप किया जायेगा ताकि किसी विशेष परिस्थिति के कारण, जैसे कि सर्दी के दौरान दिल्ली में स्मॉग की मात्रा अचानक बढ़ती है, इनकी जानकारी पहले से हो सके।

परिवहन विभाग

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली के डीटीसी और क्लस्टर बस सहित संपूर्ण बस बेड़े को वातावरण अनुकूल फ्यूल टेक्नोलाजी की ओर ले जाने के प्रति संकल्पबद्ध है। आगामी वर्ष में दिल्ली में 1000 इलेक्ट्रिक बसें लाने की तैयारी है। यह देश के किसी भी शहर में इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा। वस्तुतः चीन को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश में सबसे बड़ा।

इसके साथ-साथ परिवहन विभाग मेट्रो स्टेशन्स के पास लास्ट-माइल-कनेक्टिविटी देने के लिए डीएमआरसी के बेड़े में भी 905 इलेक्ट्रिक फीडर व्हीकल शामिल कराने में मदद कर रहा है। 2016-17 के बजट में ई-रिक्शा मालिकों को 30,000 रुपये की एकबारगी सब्सिडी देने की घोषणा की गई थी। अब सरकार ने यह फैसला किया है कि यह

लाभ उन सभी ई-रिक्शा मालिकों को भी दिया जाए जो 1 जुलाई 2015 से 1 अप्रैल 2016 के बीच पंजीकृत किए गये हैं। इस तरह 1 जुलाई 2015 से 1 अप्रैल 2016 के बीच पंजीकृत सभी ई-रिक्शा मालिकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, भले ही उनके आवेदन विभाग में विचाराधीन हों या उन्होंने नए सिरे से आवेदन किया हो। इसके अतिरिक्त एयर-एंबीयंस-फंड से 15,000 रुपये उन ई-रिक्शा मालिकों को भी दिए जाएंगे जिन्हें 15,000 रुपये की पुरानी दर से भुगतान किया गया था।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और बढ़ावा देने के लिए सरकार विस्तृत इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार कर रही है इसमें खास करके बीएस-2 एवं बीएस-3 दोपहिया वाहनों, टैक्सी और कमर्शियल गुड्स कैरियर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने का खाका बनाया जायेगा। निजी उपयोग के लिए खरीदी जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों पर तो सरकार पहले ही सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही निजी कारों के खरीदारों के लिए पेट्रोल अथवा डीजल की जगह सीएनजी-फैक्ट्री-फिटेड कार खरीदने पर सरकार 50 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन चार्ज में छूट का प्रावधान करेगी।

दिल्ली में ओवरलोडेड ट्रक्स के खिलाफ अभियान चलाने के लिए परिवहन विभाग के एनफोर्समेंट विंग को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए बुराड़ी, सराय काले खां और द्वारका स्थित इंपाउंडिंग पिट्स पर वेंडिंग-ब्रिज बनाये जायेंगे। निगरानी के लिए 60 नये वाहन, बाडी-कैमरा और ई-चालानिंग टैब खरीदे जायेंगे।

वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पोल्यूशन-अंडर-कन्ट्रोल (पीयूसी) प्रोग्राम को और प्रभावशाली बनाया जा रहा है इसके तहत वाहन मालिकों को एसएमएस अथवा फोन से रिमाइंडर भेजना और पीयूसी सेंटर्स का थर्ड-पार्टी-ऑडिट कराने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलाजी संस्थान एमआईटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्चर्स के साथ काम किया जा रहा है।

लोक निर्माण विभाग

दिल्ली में सड़क किनारे और वाहनों से उड़ने वाली धूल, प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। इस वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार लोक निर्माण विभाग की सड़कों की लैंडस्केपिंग की योजना ला रही है। इसके तहत सड़क पर धूल न उड़े, इसके लिए सड़कों के आस-पास





की सभी कच्ची जगहों को घास व पौधे लगाकर उसे सुसज्जित किया जायेगा।

लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर लगी लाइट्स को एलईडी लाइट्स में बदलने का काम एस्को मॉडल के तहत किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर एक पायलट योजना के तहत 16 कि.मी. लंबे साइकिल ट्रैक पर सौर ऊर्जा पैनल लगाये जायेंगे।

ऊर्जा

तीन साल पहले सरकार ने आते ही दिल्ली के आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आधे दाम में बिजली उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था। और तब से यानी पिछले 3 साल में दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं। यह अपने आप में एक रिकार्ड है। सस्ती बिजली से दिल्ली के आम आदमी के परिवार की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती ही है, दिल्ली की ओवर-ऑल इकोनोमी पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आज दिल्ली में करीब 37.28 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 3 साल पहले के मुकाबले आधे दाम पर बिजली मिल रही है जो कि दिल्ली में घरेलू उपभोक्ताओं का 82.84 प्रतिशत हैं। यह योजना आगे भी जारी रहेगी और इसके लिए बजट में 1,720 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

ऊर्जा विभाग के अंतर्गत रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कई ऐसी पहल की जा रही हैं जिससे फॉसिल-फ्यूल आधारित बिजली उत्पादन पर दिल्ली की निर्भरता कम से कम हो सके। दिल्ली में कुल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता फरवरी 2018 तक 133.13 मेगावाट थी, जिसमें 81.13 मेगावाट सौर ऊर्जा और 52 मेगावाट कचरे से ऊर्जा संयंत्रों से मिलने वाली बिजली शामिल है। 74 मेगावाट सौर ऊर्जा संवर्धन का कार्य प्रगति पर है। इससे दिल्ली में कार्बन एवं अन्य प्रदूषणकारी

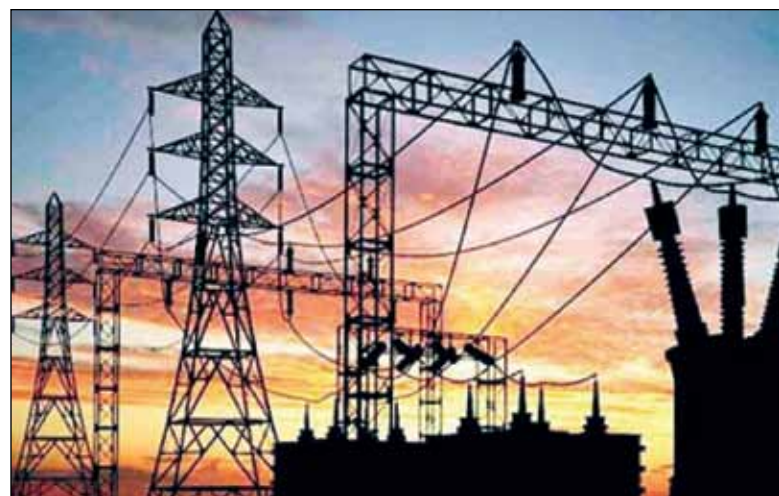
तत्वों का उत्सर्जन नीचे लाने में सफलता मिलेगी।

सरकार सौर एवं पवन आधारित बिजली उत्पादन केन्द्रों से आने वाले वर्षों में 1,000 मेगावाट ग्रीन पावर खरीदेगी। दिल्ली में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सीमित समय के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं द्वारा लगाये गये सौर ऊर्जा नेट मीटर कनेक्शन से, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, तीन साल के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से सौर ऊर्जा खरीदने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

सरकार स्कूलों, मंडियों और विभिन्न सरकारी इमारतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने के लिए एक ग्रुप-नेट-मीटरिंग पॉलिसी लायेगी ताकि दिल्ली में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा का सदुपयोग किया जा सके।

इस वर्ष के ग्रीन बजट में सरकार पायलट स्तर पर एग्रीकल्चर-कम-सोलर-फार्म-स्कीम के नाम से एक नई योजना ला रही है। इसके तहत दिल्ली के खेतों में फसल की ऊंचाई से ऊपर उठा कर सोलर पैनल स्थापित करने को प्रोत्साहन देने की योजना है। इस पर दुनिया भर में प्रयोग हो रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि इसमें किसान सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ अपनी खेती भी जारी रख पाते हैं। इससे दिल्ली में खेती-बाड़ी में लगे लोगों को अतिरिक्त आय होगी।

सरकार बिल्डिंग एनर्जी एफिसेंसी प्रोग्राम अगले साल से लागू करने जा रही है। इसके तहत विभिन्न कार्यालयों, इमारतों का पावर कंजम्पशन ऑडिट किया जायेगा। इसकी



शुरुआत ऊर्जा विभाग अपने अधीन इमारतों से करेगा। सरकार अगले वर्ष से दिल्ली में बनने वाली

नई कमर्शियल बिल्डिंग्स पर बिजली खपत कम करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड (इसीबीसी) लागू करेगी। यह कोड 100 किलोवाट या उससे अधिक की खपत वाली इमारतों या 500 वर्गमीटर से बड़े प्लॉट पर बनी इमारतों पर लागू होगा।

परिवहन

दिल्ली में पंजीकृत निजी वाहनों की कुल संख्या अन्य महानगरों में पंजीकृत निजी वाहनों की संख्या से बहुत अधिक है। इससे न केवल सड़कों पर भारी वाहनों की भीड़ रहती है बल्कि सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं और ईंधन व्यर्थ होता है। इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए सरकार दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

डीटीसी कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को उनका वेतन और अन्य भत्ते समय पर सातवें वेतन आयोग के अनुसार देने का फैसला किया गया है। इसका लाभ 41,000 कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा।

2017-18 के दौरान सरकार ने अथक प्रयास करके 10,000 नये आटो परमिट को मंजूरी दी। इसमें से 8,600 परमिट जारी किये जा चुके हैं और बाकि जल्द जारी कर दिये जायेंगे।

दिल्ली में सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने 12 आटोमोटिव ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर काम शुरू किया है। मारुति सुजुकी फाउंडेशन की सहभागिता से यह योजना

2018-19 में पूरी हो जायेगी। इसका उद्देश्य है ड्राइविंग टेस्ट लेते वक्त कम से कम मानवीय हस्तक्षेप और उसकी बारीकियों को तकनीकी मदद से जांचना। सरकार अगले कुछ हफ्तों में रोड सेफ्टी पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी करेगी और जल्द ही सड़क सुरक्षा के लिए रोड सेफ्टी फंड भी स्थापित किया जायेगा।

2018-19 के दौरान डीटीसी के बेड़े में स्टैंडर्ड साइज की 1,000 बसें जोड़ने का काम शुरू हो जायेगा बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग के जरिए स्वतः किराया एकत्र करने की व्यवस्था क्लस्टर बसों में पूरी तरह लागू कर दी गई है। डीटीसी ने भी अपनी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन प्रणाली लागू करना शुरू किया है। एक ही मोबिलिटी कार्ड की सुविधा की एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत जनवरी 2018 से डीटीसी की 200 और 50 क्लस्टर बसों में शुरू की गई है। इसे अप्रैल 2018 से सभी बसों में लागू किये जाने की योजना है। इनमें ईटीएम का इस्तेमाल करते हुए किराए का भुगतान दिल्ली मेट्रो रेल कार्ड के जरिए किया जा सकेगा।

डीटीसी द्वारा खरीदी जाने वाली नई बसों और क्लस्टर योजना के तहत शामिल की जाने वाली बसों की पार्किंग के लिए 7 बस डिपो – ढिचाऊं कलां-2, बवाना सेक्टर-1, रेवला खानपुर, रानी खेड़ा-1, रानी खेड़ा-2, रानी खेड़ा-3 और द्वारका सेक्टर 22 में पूरे कर लिए गये हैं। खरखरी नहर का बस डिपो मार्च, 2018 में पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 2018-19 में 6 नये बस डिपो घुम्मन हेड़ा, मुण्डेला कलां, रोहिणी सेक्टर-37, ईस्ट विनोद नगर, बवाना सेक्टर-5 एवं वीआइयू बुराड़ी भी बनाए जाएंगे।

सरकार ने सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन के लिए कई कदम उठाए हैं। डीटीसी की रात्रि सेवा में विस्तार कर 24 मार्गों पर 85 बसें चलाई जा रही हैं जबकि पहले 8 मार्गों पर 38 बसें ही चलती थी। डीटीसी, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस चालकों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का एक कार्यक्रम निरंतर चला रहा है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए डीटीसी की बसों में 2,370 सिविल डिफेंस मार्शल और 120 होम गार्ड तैनात किये गये हैं।

शिक्षा

सरकार दिल्ली को एक शैक्षिक केंद्र बनाने की दिशा में दूरदर्शिता और ईमानदारी से काम कर रही है। 2018-19 के बजट आबंटन में शिक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक





26 प्रतिशत है। शिक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त क्लास रूम, नए स्कूल भवन, खेल के मैदान, स्वच्छ शौचालय सुविधाओं आदि के निर्माण के संदर्भ में बुनियादी ढांचा सुविधाओं के संवर्धन के लिए भारी निवेश को प्राथमिकता दी गयी है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, वर्तमान विद्यालयों में प्री-स्कूल कक्षाएं शुरू करना, शिक्षण को दिलचस्प बनाना, और शिक्षा को खेल गतिविधियों के साथ जोड़ना, आदि ऐसे सम्भावना वाले क्षेत्र हैं, जिन पर दिल्ली सरकार 2018-19 के दौरान जोर देगी। सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों में सुधार लाने, उच्चतर शिक्षा में अधिक शैक्षिक अवसर प्रदान करने, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के जरिए उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

श्री सिसोदिया ने कहा कि सरकार ने पहले साल में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने का काम तेजी से किया। अब यह काम अपनी गति पकड़ चुका है। इसके बाद दूसरे व तीसरे वर्ष से शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें विश्वस्तरीय ट्रेनिंग दिलाने का काम शुरू किया। यह कार्य भी अब अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। अगले साल से हमारी सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक नया पाठ्यक्रम – हेप्पीनेस करिकुलम के नाम से लेकर आ रही है। इसके तहत नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां विकसित की जा रही हैं, ताकि कम आयु में ही बच्चों को प्रसन्न रहने, आत्मविश्वास अर्जित करने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने का प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके लिए पाठ्यक्रम में ऐसे घटक शामिल किए जाएंगे, जो आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने वाले और तनाव एवं चिंता कम करने वाले हों और साथ ही निराशा से बचने में मददगार और शिक्षा

एवं कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता सृजित करने वाले, रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने वाले हों। शिक्षा में ऐसा समग्र दृष्टिकोण अपनाने से बच्चों के स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण और उन्हें खुशहाल जिंदगी जीने में सक्षम बनाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो बदलाव आया है उसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानि एसएमसी का बड़ा योगदान रहा है। एसएमसी के 16 सदस्यों में से 12 अभिभावक होते हैं। इस सामुदायिक भागीदारी से स्कूलों में जवाबदेही बढ़ी है। इसलिए इस वर्ष से हर स्कूल की एसएमसी को 5 लाख रुपये का फंड दिया जायेगा जिससे वो स्कूल में लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदने, पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए शिक्षकों की सुविधा हेतु टीचिंग ऐडस खरीदने व छोटी-मोटी मरम्मत के काम करा सकेगी। साथ ही एसएमसी शॉर्ट-टर्म-बेसिस पर रिसोर्स पर्सन रख पायेगी। जो छात्रों को म्यूजिक, आर्ट, डांस, आईआईटी-मेडिकल की तैयारी या एक्सट्रा क्लास करा सकेगी। इस फंड के इस्तेमाल के निर्णय एसएमसी की मीटिंग में ही होंगे। इसके लिए स्कूल किसी पर निर्भर नहीं होगा।

पिछले 2 सालों में मेगा पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों को स्कूलों से जोड़ने का प्रयास किया गया है क्योंकि सरकार मानती है कि शिक्षा सफल होने के लिए स्कूल और घर के सम्मिलित प्रयास की जरूरत है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए अब हम सरकारी स्कूलों में पैरेंट्स वर्कशॉप भी शुरू करेंगे ताकि माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई में सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका निभा सकें।

शिक्षा अधिकार अधिनियम के संदर्भ में स्टूडेंट-टीचर अनुपात बनाए रखने के लिए शैक्षिक ढांचे में निरंतर बढ़ोतरी के प्रयास किए गए हैं। 12,748 अतिरिक्त क्लासरूमस के निर्माण, 30 नए स्कूल बिल्डिंग और 366 सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी कक्षाएं शुरू करने की योजना बनाई गई है। 155 सर्वोदय विद्यालयों में प्री-प्राइमरी कक्षाएँ पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। इसके साथ ही सरकार ने 144 स्कूलों में वाणिज्य विषय की पढ़ाई भी शुरू की है।

एलीमेंट्री कक्षाओं के बच्चों द्वारा अपनी टेक्सटबुक पढ़ने और बेसिक मैथ स्किल डेवलप करने के उद्देश्य से सरकार ने 'चुनौती 2018' कार्यक्रम शुरू किया था। इसके अच्छे नतीजों

को देखते हुए अब इसी तर्ज पर 'मिशन बुनियाद' के नाम से कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके

तहत दिल्ली सरकार और नगर निगम के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की रीडिंग और मैथ स्किल्स ठीक करने पर अप्रैल, मई और जून के महीनों में विशेष अभियान चलाया जायेगा।

विद्यार्थियों की संरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने और स्कूल गतिविधियों पर समुचित निगरानी रखने के लिए सभी सरकारी स्कूल भवनों में करीब 1.2 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए 2018-19 के बजट अनुमानों में 175 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। प्रत्येक भवन में 150 से 200 तक कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें खास बात यह भी है कि अभिभावकों को अपने बच्चों के क्लासरूम की गतिविधियां सीधे इंटरनेट पर देखने की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।

अध्यापकों को विश्वस्तरीय ट्रेनिंग के साथ-साथ सरकार उन्हें आधुनिक सुविधायें देने पर भी जोर दे रही है। अभी तक अध्यापकों का बहुत सारा समय हर महीने बच्चों की सूचियां बनाने व रिजल्ट तैयार करने, उसे अपलोड करने आदि में व्यर्थ जाता है। सरकार सभी स्कूल अध्यापकों को कम्प्यूटर टेबलेट (टैब) देगी ताकि सभी अध्यापक अपने स्कूल के बच्चों का ऑनलाईन रिकार्ड रख सकें। उनकी उपस्थिति, रिजल्ट, स्कॉलरशिप आदि का डाटा तैयार कर सकें और डिपार्टमेंट में भेजने के लिए अलग-अलग सूचियां न तैयार करनी पड़ें। इस टैब का इस्तेमाल टीचर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में भी होगा। अध्यापकों की सुविधा के लिए स्कूलों में मॉडर्न

स्टाफरूम बनाने और उसमें कॉफी मशीन इत्यादि लगाने का काम चल रहा है।

सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस शुरू होंगी ताकि उनके अंदर विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को सुरक्षित बनाये रखने का आत्मविश्वास हो और वो किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए शारारिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हों। इसके लिए शिक्षा विभाग के बजट में 10 करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था की गई है।

इस साल से दिल्ली सरकार एक नई योजना ला रही है जिसके तहत दिल्ली के हर स्कूल का मूल्यांकन कराया जायेगा उनके बीच पढ़ाई की व्यवस्था और माहौल को लेकर स्वस्थ कम्पीटिशन होगा और लोगों के पास स्कूल से संबंधित अधिकारिक सूचनायें होंगी। ताकि स्कूलों को सही दिशा में आगे बढ़ाने का रोडमैप तैयार किया जा सके। इस मकसद के लिए सरकार ने शिक्षा विभाग के माध्यम से 15 करोड़ रुपये डी.सी.पी.सी.आर. को देने का फैसला किया है।

डिफेंस सर्विसिस में युवाओं की रुचि जगाने के लिए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कैडेटों को प्रशिक्षण की अवधि में 3 वर्ष के लिए प्रति माह 2000 रुपये की वित्तीय सहायता/प्रशिक्षण भत्ता देने का निर्णय किया है।

वित्तमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय स्कूल खेलों में दिल्ली इस बार भी शीर्ष पर रहा और उसने इन खेलों में कुल मिलाकर 426 स्वर्ण पदक, 205 रजत और 169 कांस्य पदक जीते। सरकार उदीयमान खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय खेल ढांचे का निर्माण करने के लिए वचनबद्ध है। खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने में खिलाड़ियों की सहायता के लिए वर्ष 2018-19 में सरकार दो नए कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। ये हैं - "खेलो और तरक्की करो" और "मिशन एक्सिलेंस" यानि उत्कृष्टता अभियान। "खेलो और तरक्की करो" कार्यक्रम के अंतर्गत 14 से 17 वर्ष की आयु समूह के ऐसे खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो राष्ट्रीय रैंकिंग-अलग-अलग खेलों में रेटिंग की दृष्टि से शीर्ष पर हों और उन्होंने दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया हो। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। "मिशन एक्सिलेंस" कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी आयु समूह के खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करने



के लिए तैयार करने के वास्ते वित्तीय सहायता दी जाएगी। इन दोनों कार्यक्रमों के लिए 2018-19 के बजट में 35 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

स्थानीय स्तर पर मोहल्ला एवं कालोनियों में खेलों में जनता को प्रोत्साहित करने एवं भाग लेने के लिए विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में खेल-कूद आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के लिए 2018-19 में 20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईआईटी के कैम्पस के निर्माण का दूसरा चरण 250 करोड़ रुपये की लागत से पूरे जोर-शोर से जारी है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।

आईआईआईटी में दाखिले के लिए सीटों की संख्या 1,200 से बढ़ाकर 2,500 की जा सकेगी। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टैंडीज का निर्माण कार्य 132.47 करोड़ रुपये की लागत से पूरा कर लिया गया है। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय-डीटीयू का पूर्वी कैम्पस चालू हो गया है, जिसमें 300 सीटें हैं, जिन्हें मिलाकर डीटीयू में सीटों की संख्या, जो 2014-15 में 2,564 थी, वह 2017-18 में बढ़कर 3,689 हो गई।

रोहिणी और धीरपुर में अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नए कैम्पस का निर्माण कार्य 2018-19 में शुरू करने की योजना है। गुरु गोंविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पूर्वी कैम्पस का निर्माण अगस्त 2017 में 271 करोड़ रुपये की लागत से सूरजमल विहार में शुरू किया गया है।

जीजीएसआईपीयू में सीटों की कुल संख्या 2017-18 में बढ़कर 34,094 हो गई। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए पूर्वी परिसर ने शैक्षिक वर्ष 2017-18 से काम करना शुरू कर दिया। दूसरे चरण के दौरान दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और एनएसआईटी के मौजूदा परिसरों का विस्तार करने और सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना है।

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में गर्व के साथ साझा किया कि विश्वस्तरीय कौशल विकास केंद्र जो कि आइटीई, सिंगापुर के सहयोग से शुरू किया गया है, ने शत-प्रतिशत प्लेसमेंट यानी नौकरी दिलाने का रिकार्ड निरंतर बनाए रखा है और कौशल विकास कार्यक्रम का मॉडल सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। सरकार ने कौशल मॉडल का अनुकरण करने का निर्णय किया है, जिसके तहत दिल्ली में 25 नए विश्व स्तरीय कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसका लक्ष्य हर वर्ष करीब 25,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि 2018-19 के दौरान 25 नए विश्व स्तरीय कौशल विकास केन्द्र खोलने की योजना है।

उच्चतर शिक्षा को अफोर्डेबल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सात विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध



कॉलेजों / संस्थानों के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए “योग्यता एवं आर्थिक स्थिति संबंधी वित्तीय सहायता” नामक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड रखने वाले विद्यार्थियों को शत प्रतिशत ट्यूशन फीस के समकक्ष वित्तीय सहायता

दी जाती है। जो विद्यार्थी किसी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कवर न किए गए हों, और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम हो, वे भी ट्यूशन फीस की आधी राशि (50 प्रतिशत) के समान राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। 2.50 लाख रुपये से अधिक लेकिन 6 लाख रुपये तक वार्षिक परिवार आय वाले विद्यार्थी इस कार्यक्रम के अंतर्गत ट्यूशन फीस के 25 प्रतिशत के समान वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

दिल्ली में 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्चतर शिक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों को ऋण सहायता देने क

लिए 2016-17 में सरकार ने दिल्ली उच्चतर शिक्षा और कौशल विकास लोन गारंटी कार्यक्रम शुरू किया

था। अब इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए इसके दायरे में अन्य राज्यों-दिल्ली से बाहर, लेकिन भारत में स्थित केंद्रीय संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है।

दिल्ली, निस्संदेह, समृद्ध धरोहर और संस्कृति का खजाना है। दिल्ली की धरोहर के संबंध में दुनिया भर के रिसर्चर्स को अवगत कराने और उन्हें आगे की रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने आर्काइवल रिकार्ड्स के डिजिटाइजेशन करने और उनकी माइक्रो फिल्म बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। यह परियोजना सात महीने पहले शुरू की गयी थी और अब तक 20 लाख आर्काइवल रिकार्ड्स का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। अप्रैल 2018 तक यह सेवा देश और दुनिया के रिसर्चर्स के लिए उपलब्ध हो जायेगी।

दिल्ली में कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2018-19 में कुछ नए कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव है। नए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए इस वर्ष बजट में 36 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में 13 नई भाषा अकादमियों की स्थापना, एक अंग्रेजी भाषा की अकादमी और राज्य स्तरीय नृत्य एवं गायन प्रतिभा खोज के लिए वार्षिक शृंखलाओं का आयोजन, सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन और पुरातत्व एवं अभिलेख में रिसर्च फ़ैलोशिप आदि शामिल हैं।

स्वास्थ्य

दिल्ली में 3 स्तरीय स्वास्थ्य ढांचा विकसित किया जा रहा है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक, पोलिक्लिनिक और अस्पताल शामिल हैं। दिल्ली के नागरिकों को उनके निवास के निकट स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अभी तक 164 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए जा चुके हैं। अब तक करीब 80 लाख व्यक्तियों ने मोहल्ला क्लिनिकों में उपचार सेवाओं का लाभ उठाया। मोहल्ला क्लिनिकों की स्थापना के लिए 530 स्थानों का चयन किया गया है और सरकार का लक्ष्य 1,000 मोहल्ला क्लिनिकों का निर्माण करने का है। इसी प्रकार 24 पॉलिक्लिनिक काम कर रहे हैं और 94 औषधालयों की पहचान की गई है, जहां ऐसे



पॉलिक्लिनिक शुरू किए जाएंगे। इससे सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम किया जा सकेगा।

सरकार दिल्ली के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या मौजूदा 10,000 से बढ़ाकर 20,000 पर पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। अम्बेडकर नगर में 600 बिस्तर का अस्पताल और बुराड़ी में 800 बिस्तर का अस्पताल वर्ष 2018-19 में तैयार हो जाएगा। द्वारका में 1,500 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण कार्य अग्रिम चरण में है। दिल्ली सरकार के सात मौजूदा अस्पतालों में 2,546 नए बिस्तर जोड़े जाएंगे। मादीपुर, ज्वालाहेड़ी, हस्तसाल, सरिता विहार, दीनदारपुर, केशवपुरम और छतरपुर में नए अस्पतालों के निर्माण की योजना तैयार की जा रही है।

दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाले रोगियों के डॉयग्नोस्टिक-टेस्ट निःशुल्क किये जाते हैं। इतना ही नहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा रैफर किए जाने पर निर्दिष्ट सूचीबद्ध प्राइवेट केन्द्रों में एमआरआई, सीटी, पीईटीसीटी, रेडियो न्यूक्लियर स्कैन, अल्ट्रासाउंड, कलर डोपलर, इको, टीएमटी, ईईजी और ईएमजी जैसी रेडियोलॉजिकल सेवाएं भी सभी रोगियों के लिए निःशुल्क हैं।

सरकार ने दिल्ली में हुई सड़क दुर्घटनाओं के सभी पीड़ितों, एसिड हमलों के पीड़ितों और थर्मल या तपन से जले घायलों के खर्च की लागत वहन करने का भी निर्णय लिया है, भले ही ऐसे पीड़ित व्यक्ति की आमदनी कितनी ही क्यों न हो और वह कहीं का भी रहने वाला हो। इसके अलावा, दिल्ली सरकार के 24 अस्पतालों को अधिकृत किया गया है कि वे रोगियों को 48 सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क शल्यचिकित्सा के लिए भेज सकते हैं।

भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में कोई दुर्घटना होने या अन्य आपात स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने के लिए “प्रथम मददगार वाहन”—फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल (एफआरवी) प्रदान करने के एक प्रायोगिक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। प्रशिक्षित ऐम्बुलेंस कार्मिकों द्वारा संचालित 16 मोटरसाइकिलों के साथ यह कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली में शुरू किया जाएगा। इससे तंग गलियों और भीड़ भरे क्षेत्रों में बचाव कार्रवाई शीघ्र संचालित करने में मदद मिलेगी।

सभी विधानसभा क्षेत्रों में रोगी कल्याण समितियां बनायी जाएंगी और प्रत्येक जन स्वास्थ्य केन्द्र जैसे मोहल्ला क्लिनिक, पोलिक्लिनिक और दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियों व सीड पीयूएचसी में उसकी उप-समिति के रूप में एक जन स्वास्थ्य समिति गठित की जायेगी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रबंधन में बेहतर सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने वाले मोबाइल वैन क्लिनिकों की स्थापना की जाएगी जो विशेष रूप से आंख और कान संबंधी सेवाएं प्रदान करेंगे। वर्ष 2018-19 में इस कार्यक्रम के लिए 15 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार दिल्ली के नागरिकों को सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए ‘सबके लिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ शुरू करेगी। इस कार्यक्रम के विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

सरकार समाज के निर्धन और उपेक्षित वर्गों, विशेष रूप से संकट ग्रस्त महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों,

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण

के प्रति वचनबद्ध है और तदनुरूप उनके कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम लागू कर रही है। सरकार करीब 7 लाख लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन संकटग्रस्त महिलाएं, विधवाएं आदि शामिल हैं। सरकार ने एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 10,897 आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवाओं का स्तर बढ़ाने का निर्णय किया है, जो लगभग 12 लाख बच्चों और महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण और स्कूल-पूर्व गतिविधियों से संबद्ध आदि को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

सरकार सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाएगी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन उपलब्ध कराएगी, जिससे आईसीडीएस परियोजना के अंतर्गत सेवाओं और कार्यक्रमों की समुचित निगरानी और रिपोर्टिंग करने में मदद मिलेगी। 2018-19 के दौरान “प्रोत्साहित आंगनवाड़ी उन्नयन कार्यक्रम” के अंतर्गत विभाग बच्चों के लिए मेज, कुर्सी, चटाईयाँ, खिलौने आदि उपलब्ध कराते हुए मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाएगा। एक नया कार्यक्रम “अर्ली-चाइल्डहुड-एजुकेशन के बारे में अभिभावकों और आंगनवाड़ी समितियों के लिए प्रशिक्षण” भी शुरू किया जाएगा।

अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक से संबंधित छात्रों के लिए ‘लाडली योजना’ के पैटर्न पर 18 वर्ष की आयु तक के छात्रों के नाम पर फिक्स्ड डिपोजिट योजना शुरू की जाएगी। सरकार ने “जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना” नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत दिल्ली के स्कूल से कक्षा 10वीं व 12वीं पास या कक्षा 12वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्रदान की जाती है ताकि वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर सकें। ऐसे अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक हो और यदि परिवार की आय 6 लाख रुपये तक होगी तो सरकार 75 प्रतिशत फीस वहन करेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को 2,500 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड, कोचिंग के दौरान 4 से 5 माह तक दिया जाएगा।



सरकार ने एक नया कार्यक्रम “अल्कोहल और नशीले पदार्थों की रोकथाम” शुरू करने का निर्णय किया है।

इसका उद्देश्य दिल्ली में नशे की लत छुड़ाने और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करना और इस दिशा में पूरक उपाय करना है। इस कार्यक्रम में समुदाय आधारित संगठनों की मदद ली जाएगी।

जलापूर्ति और सीवर

पिछली बार के आउटकम बजट के रिव्यू में यह बात सामने आयी कि दिल्ली में 47 प्रतिशत पानी, नॉन रिवेन्यू वाटर



है। यानी दिल्ली जल बोर्ड को अपने करीब आधे पानी का यही पता नहीं है कि वह लीक हो रहा है या चोरी हो रहा है। पहली बार सरकार पूरी दिल्ली में बल्क वाटर मीटर लगाने का प्रोजेक्ट लेकर आयी है ताकि पता चले पानी जा कहां रहा है। सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सभी प्राइमरी और सैकेंडरी यूजीआर और सभी टैपिंग पर मीटर लगाये जायेंगे। इससे पानी की चोरी पकड़ी जा सकेगी और एक तरह से रोजाना पानी का आडिट होगा। इस बल्क वाटर मीटर्स का पूरा डेटा वेबसाइट पर डाला जाएगा ताकि दिल्लीवासियों को भी पता रहे कि उनकी कालोनी में दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कितना पानी आ रहा है और वह कहां जा रहा है।

दिल्ली सरकार सीवेज ट्रीटमेंट की पूरी अवधारणा को बदलने पर काम कर रही है। पहले दिल्ली में बड़े-बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये गये हैं। इनसे ट्रीट होकर पूरी दिल्ली में लगभग 450 एमजीडी पानी दिल्ली जल बोर्ड के पास उपलब्ध होता है। लेकिन इसमें से केवल 89 एमजीडी पानी ही अभी इस्तेमाल हो रहा है और बाकि का 361 एमजीडी पानी रोजाना यमुना में बहा दिया जाता है। इस

पानी को पीने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता लेकिन दिल्ली को हरा-भरा बनाने के लिए सड़कों के किनारे और पार्कों में बागवानी, वर्कशॉप, इंडस्ट्रीयल कूलिंग टॉवरस आदि में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

अब सरकार पूरी दिल्ली में छोटे-छोट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगायेगी। जैसे एक कालोनी में छोटा एसटीपी लगाया जायेगा उससे निकलने वाले साफ पानी को वहीं लोगों के घरों में शौच आदि के लिए, उस क्षेत्र में हरियाली के लिए अथवा किसी वाटर बॉडी में इस्तेमाल किया जायेगा। बुराड़ी, छतरपुर, किराड़ी, नरेला, जींदपुर, पल्ला, बवाना, कंझावला, बदरपुर, मुंडका और नजफगढ़ की विभिन्न कालोनियों में ये प्रोजेक्ट्स लगाये जायेंगे।

सीवर लाइनों की वाहक क्षमता में सुधार के लिए 162 किलोमीटर पेरीफेरियल सीवर लाइन का चयन ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें नया रूप देने के लिए किया गया है। इससे पुरानी सीवर लाइनों का जीवनकाल 50 वर्ष तक बढ़ जाएगा।

आवास और शहरी विकास

सरकार अनियमित कालोनियों में सड़कों और नालियों का निर्माण, जलापूर्ति, सीवर प्रणाली, स्वच्छता और गलियों में प्रकाश आदि बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दे रही है। इन कार्यों के लिए मुख्य रूप से कार्यान्वयन एजेंसियों को धन दिया जा रहा है, जिनमें डीएसआईआईडीसी, आई एंड एफसी और दिल्ली जल बोर्ड शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने 11 दिसंबर, 2017 को दिल्ली स्लम और जेजे पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों का उसी भूमि पर पुनर्वास करना अथवा 5 किलोमीटर के दायरे में बनाए गए प्लैटों में पुनर्स्थापना करना है। 2017-18 के दौरान 1,600



जेजे परिवारों को द्वारका और बापरोला में स्थानांतरित किया गया।

झुग्गी निवासियों के लिए निकटवर्ती सुसंचालित और सुरक्षित शौचालयों के इस्तेमाल की व्यवस्था के लिए पिछले 3 वर्षों में करीब 16,000 शौचालय सीटों का नवीकरण या निर्माण किया गया। 1 जनवरी, 2018 से इन शौचालय परिसरों को स्लम निवासियों के लिए निःशुल्क दिन-रात इस्तेमाल हेतु उपलब्ध कराया गया है।

सड़क एवं अन्य आधारभूत ढांचा

पिछले दिनों, बाहरी रिंग रोड पर विकासपुरी से वजीराबाद तक एलेवेटेड कोरिडोर को सिग्नल मुक्त किया जा चुका है। इससे विकासपुरी से वजीराबाद तक यात्रा समय में लगभग 45 मिनट की बचत हो रही है। बारापूला नाला (चरण-2) का निर्माण कार्य मार्च 2018 तक पूरा होने की आशा है। इससे रिंग रोड पर वाहनों की भीड़-भाड़ से निजात मिलेगी और यात्रा समय में 15 से 20 मिनट की बचत होगी। सराय काले खां से मयूर विहार तक बारापूला नाला (चरण 3) के एलेवेटेड रोड का निर्माण कार्य दिसंबर 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना पर 1260 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह एलेवेटेड रोड बनने से यात्रा समय में 10-12 मिनट कम लगेंगे जबकि अभी इसमें आधा घंटा लगता है। ककरोला मोड़ से वजीराबाद तक नजफगढ़ नाले के साथ-साथ एलेवेटेड रोड का निर्माण कार्य 2018-19 के दौरान शुरू कर दिया जाएगा।

आईटीपीओ से भैरों रोड-रिंग रोड जंक्शन से पुराना किला रोड के नीचे 700 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद इंडिया गेट से रिंग रोड पहुंचना आसान हो जाएगा और यात्रा समय में 10-15 मिनट तक की कमी आएगी।

यमुना और आगरा नहर के साथ-साथ डीएनडी फ्लाईओवर और फरीदाबाद के बीच कालिंदी बाईपास

का निर्माण कार्य भी 2018-19 में शुरू कर दिया जाएगा। सिग्नेचर ब्रिज से कालिंदी कुंज बाईपास तक एलेवेटेड रोड का निर्माण कार्य भी 2018-19 में शुरू हो जाएगा। इससे वजीराबाद और डीएनडी फ्लाईओवर के बीच रिंगरोड पर यातायात कम होगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद इस मार्ग पर यात्रा समय में 20-30 मिनट की कमी आएगी।

सरकार ने दिल्ली में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। वाई-फाई सुविधा को जल्दी उपलब्ध कराने के लिए यह प्रोजेक्ट आईटी विभाग से लेकर लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। इसके लिए बजट में सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

विकास

दिल्ली के सभी गांवों के चहुँमुखी विकास के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया गया है। माननीय विधायक अपनी ग्राम विकास परियोजनाओं की स्थिति के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकें, इसके लिए एनआईसी की सहायता से एक एप्प विकसित किया जाएगा।

सरकार दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में हाईटेक डेमोन्स्ट्रेशन फार्मों के विकास के लिए एक नई योजना-स्मार्ट कृषि योजना लागू करेगी। इनसे किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए विकसित की गई नई तकनीकों और फसलों की किस्मों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे और उनका इस्तेमाल कर सकेंगे।

दिल्ली में अगले वर्ष मार्च यानी मार्च 2019 से सड़कों पर ई-बसें चलने लगेंगी। 1000 नई डीटीसी बसें खरीदने की





समय सीमा भी सरकार ने तैयार कर ली है। 11 मई तक इसके बिड्स जमा करा लिये जायेंगे। उसके बाद बिड खोलना, फाइनैन्शियल बिड आदि की प्रक्रिया पूरी करते हुए 20 जुलाई तक वर्क-ऑर्डर जारी कर दिये जायेंगे। 20 नवम्बर तक 40 बसों की पहली खेप आ जायेगी और इसके बाद 120 बस प्रतिमाह के आधार पर अगले 8 महीने में 960 बसें दिल्ली की सड़कों पर आ जायेगी।

इसी तरह 1000 नई कलस्टर बसें भी जोड़ने की समय सीमा भी सरकार ने तैयार कर ली है। इसकी टेक्नीकल बिड्स अभी जमा हो रही हैं। 6 अप्रैल तक फाइनैन्शियल बिड्स खोल ली जायेंगी और 30 अप्रैल तक कैबिनेट से मंजूरी लेकर 31 मई तक लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया जायेगा। सितम्बर 2018 से नवम्बर 2018 के बीच अलग-अलग सैक्टर्स में 251 बसें और उसके बाद दिसम्बर 2018 से फरवरी 2019 के बीच बाकी 749 बसें दिल्ली की सड़कों पर आ जायेंगी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लीनिक बनाने की भी समय सीमा तय कर ली गयी है। 530 मोहल्ला क्लीनिक तथा 230 स्कूलों में स्कूल क्लीनिक बनाने का काम 30 अक्टूबर 2018 तक पूरा कर लिया जायेगा। इसके बाद अगले 4 महीनों में इसमें स्टाफ की नियुक्ति कर सभी मोहल्ला क्लीनिक्स को चालू कर दिया जायेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र की एक और महत्वपूर्ण योजना हास्पिटल इंफोर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी एचआईएमएस बनाने की है। एचआईएमएस लागू करने के लिए आरएफपी 30 जून 2018 तक जारी कर दी जायेगी। इसका टेंडर 30 सितम्बर 2018 तक अवार्ड कर दिया जायेगा। पूरी दिल्ली के लिए साफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के काम में करीब 6 महीने लगेंगे। इसके बाद ट्रेनिंग, ट्रायल, हार्डवेयर परचेज आदि पूरा कर इस योजना को 1 जुलाई 2019 से लागू किया जायेगा।



विभिन्न सरकारी सेवाओं की डोर-स्टेप-डिलीवरी की भी समय सीमा तय कर ली गयी है। टेंडर की जांच, टेक्नीकल बिडिंग व फाइनैन्शियल बिड आदि का काम अप्रैल माह में पूरा कर 1 मई 2018 तक चयनित कम्पनी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया जायेगा और 15 जून 2018 से यह योजना लागू हो जायेगी।

सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की परियोजना पर काम चल रहा है। इसका टेंडर 15 जून, 2018 तक अवार्ड कर दिया जायेगा। परियोजना कार्य 15 जुलाई 2018 को शुरू होने और जनवरी 2019 के अंत तक पूरा हो जाने का अनुमान है। इससे पूर्व, इस परियोजना का 7 अप्रैल 2018 तक प्रारंभिक अनुमान जमा करने तथा 22 मई 2018 तक प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय मंजूरी प्रदान करने की संभावना है।

गरीबों को राशन देने की योजना देश में काफी लोकप्रिय है। लेकिन इसके बारे में कड़वा सच यह भी है कि इसका एक बड़ा हिस्सा चोरी चला जाता है। दिल्ली सरकार एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए गरीब लोगों को दिया जाने वाला राशन सीधे उनके घर पहुंचाने की योजना लेकर आ रही है। डोर-स्टेप-डिलीवरी-ऑफ-राशन नाम की इस योजना से गरीब लोगों के राशन की चोरी रुकेगी, उनको फायदा होगा। ■



23 मार्च, शहीद दिवस पर विशेष



भगत सिंह के चार पत्र

पिता के नाम पत्र

4 अक्तूबर, 1930

(30 सितम्बर, 1930 को भगतसिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने ट्रिब्यूनल को एक अर्जी देकर बचाव पेश करने के लिए अवसर की माँग की। सरदार किशनसिंह स्वयं देशभक्त थे और राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल जाते रहते थे। उन्हें व कुछ अन्य देशभक्तों को लगता था कि शायद बचाव-पक्ष पेश कर भगतसिंह को फाँसी के फन्दे से बचाया जा सकता है, लेकिन भगतसिंह और उनके साथी बिल्कुल अलग नीति पर चल रहे थे। उनके अनुसार, ब्रिटिश सरकार बदला लेने की नीति पर चल रही है व न्याय सिर्फ ढकोसला है। किसी भी तरीके से उसे सजा देने से रोका नहीं जा सकता। उन्हें लगता था कि यदि इस मामले में कमजोरी दिखायी गयी तो जन-चेतना में अंकुरित हुआ क्रान्ति-बीज स्थिर नहीं हो पायेगा। पिता द्वारा दी गयी अर्जी से भगतसिंह की भावनाओं को भी चोट लगी थी, लेकिन अपनी भावनाओं को नियन्त्रित कर अपने सिद्धान्तों पर जोर देते हुए उन्होंने 4 अक्तूबर, 1930 को यह पत्र लिखा जो उनके पिता को देर से मिला। 7 अक्तूबर, 1930 को मुकदमे का फैसला सुना दिया गया।)

पूज्य पिता जी,

मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव-पक्ष के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल को एक आवेदन भेजा है। यह खबर इतनी यातनामय थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। इस खबर ने मेरे भीतर की शान्ति भंग कर उथल-पुथल मचा दी है। मैं यह नहीं समझ सकता कि वर्तमान स्थितियों में और इस मामले पर आप किस तरह का आवेदन दे सकते हैं?

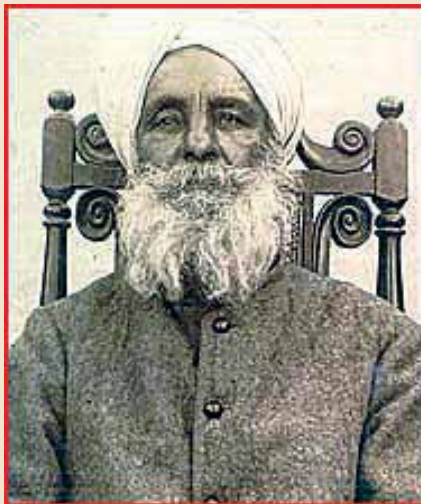
आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं और इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूँ लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि आपको मेरे साथ सलाह-मशविरा किये बिना ऐसे आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं था। आप जानते थे कि राजनैतिक क्षेत्र में मेरे विचार आपसे काफी अलग हैं। मैं आपकी सहमति या असहमति का ख्याल किये बिना सदा स्वतन्त्रतापूर्वक काम करता रहा हूँ।

मुझे यकीन है कि आपको यह बात याद होगी कि आप आरम्भ से ही मुझसे यह बात मनवा लेने की कोशिशें करते रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा संजीदगी से लड़ूँ और अपना बचाव ठीक से प्रस्तुत करूँ, लेकिन आपको यह भी मालूम

है कि मैं सदा इसका विरोध करता रहा हूँ। मैंने कभी भी अपना बचाव करने की इच्छा प्रकट नहीं की और न ही मैंने कभी इस पर संजीदगी से गौर किया है।

आप जानते हैं कि हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरा हर कदम इस नीति, मेरे सिद्धान्तों और हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। आज स्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। लेकिन अगर स्थितियाँ इससे कुछ और भी अलग होतीं तो भी मैं अन्तिम व्यक्ति होता जो बचाव प्रस्तुत करता। इस पूरे मुकदमे में मेरे सामने एक ही विचार था और वह यह कि हमारे विरुद्ध जो संगीन आरोप लगाये गए हैं, बावजूद उनके हम पूर्णतया इस सम्बन्ध में अवहेलना का व्यवहार करें। मेरा नजरिया यह रहा है कि सभी राजनैतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थितियों में उपेक्षा दिखानी चाहिए और उनको जो भी कठोरतम सजा दी जाए, वह उन्हें हँसते-हँसते बर्दाश्त करनी चाहिए। इस पूरे मुकदमे के दौरान हमारी योजना इसी सिद्धान्त के अनुरूप रही है। हम ऐसा करने में सफल हुए या नहीं, यह फैसला करना मेरा काम नहीं। हम खुदगर्जी को त्यागकर अपना काम कर रहे हैं।

वाइसराय ने लाहौर साजिश केस आर्डिनेंस जारी करते हुए इसके साथ जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस साजिश के मुजरिम शान्ति व्यवस्था को समाप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। इससे जो हालात पैदा हुए उसने हमें यह मौका दिया कि हम जनता के समक्ष यह बात प्रस्तुत करें कि वह स्वयं देख ले कि शान्ति-व्यवस्था एवं कानून समाप्त करने की कोशिशें हम कर रहे हैं या हमारे विरोधी? इस बात पर मतभेद हो सकते हैं। शायद आप भी उनमें से एक हों जो इस बात पर मतभेद रखते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझसे सलाह किए बिना मेरी ओर से ऐसे कदम उठाएं। मेरी जिन्दगी इतनी कीमती नहीं जितनी कि आप सोचते हैं। कम-से-कम मेरे लिए तो इस जीवन की इतनी कीमत नहीं कि इसे सिद्धान्तों को कुर्बान करके बचाया जाए। मेरे अलावा मेरे और साथी भी हैं जिनके मुकदमे इतने ही संगीन हैं जितना कि मेरा मुकदमा। हमने एक संयुक्त



योजना अपनायी है और उस योजना पर हम अन्तिम समय तक डटे रहेंगे। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि हमें व्यक्तिगत रूप में इस बात के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा।

पिता जी, मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे भय है, आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे बढ़कर आपके इस काम की निन्दा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएँ न लाँघ जाऊँ और मेरे शब्द ज्यादा सख्त न हो जायें। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूँगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम न मानता, लेकिन आपके सन्दर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि यह एक कमजोरी है—निचले स्तर की कमजोरी।

यह एक ऐसा समय था जब हम सबका इम्तिहान हो रहा था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप इस इम्तिहान में नाकाम रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप भी इतने ही देशप्रेमी हैं, जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है। मैं जानता हूँ कि आपने अपनी पूरी जिन्दगी भारत की आजादी के लिए लगा दी है, लेकिन इस अहम मोड़ पर आपने ऐसी कमजोरी दिखाई, यह बात मैं समझ नहीं सकता।

अन्त में मैं आपसे, आपके अन्य मित्रों एवं मेरे मुकदमे में दिलचस्पी लेनेवालों से यह कहना चाहता हूँ कि मैं आपके इस कदम को नापसन्द करता हूँ। मैं आज भी अदालत में अपना कोई बचाव प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं हूँ। अगर अदालत हमारे कुछ साथियों की ओर से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर कर लेती, तो भी मैं कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करता।

भूख हड़ताल के दिनों में ट्रिब्यूनल को जो आवेदन पत्र मैंने दिया था और उन दिनों में जो साक्षात्कार दिया था उन्हें गलत अर्थों में समझा गया है और अखबारों में यह प्रकाशित कर दिया गया कि मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, हालाँकि मैं हमेशा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के विरोध में रहा। आज भी मेरी वही मान्यता है जो उस समय थी।

बोर्स्टल जेल में बन्दी मेरे साथी इस बात को मेरी ओर से गद्दारी और विश्वासघात ही समझ रहे होंगे। मुझे उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं मिल सकेगा।

मैं चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में जो उलझनें पैदा हो गयी हैं, उनके विषय में जनता को असलियत का पता चल जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्द-से-जल्द यह चिट्ठी प्रकाशित कर दें।

आपका आज्ञाकारी,
भगत सिंह

शहादत से पहले साथियों को अन्तिम पत्र

22 मार्च, 1931

साथियो,

स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझमें भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ, कि मैं कैद होकर या पाबन्द होकर जीना नहीं चाहता।

मेरा नाम हिन्दुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊँचा उठा दिया है—इतना ऊँचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊँचा मैं हर्गिज नहीं हो सकता।

आज मेरी कमजोरियाँ जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फाँसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएँगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मद्धिम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हँसते-हँसते मेरे फाँसी चढ़ने की सूरत में हिन्दुस्तानी माताएँ अपने बच्चों के भगतसिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी।

हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका हजारवाँ भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर

स्वतन्त्र, जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फाँसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इन्तजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए।

आपका साथी
भगत सिंह

छोटे भाई कुलबीर के नाम अन्तिम पत्र

लाहौर सेण्ट्रल जेल,
3 मार्च, 1931

प्रिय कुलबीर सिंह,

तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुलाकात के वक्त ख़त के जवाब में कुछ लिख देने के लिए कहा। कुछ अल्फाज (शब्द) लिख दूँ, बस—देखो, मैंने किसी के लिए कुछ न किया, तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं। आजकल बिल्कुल मुसीबत में छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी जिन्दगी का क्या होगा? गुजारा कैसे करोगे? यही सब सोचकर काँप जाता हूँ, मगर भाई हौसला रखना, मुसीबत में भी कभी मत घबराना। इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ। अमेरिका जा सकते तो बहुत अच्छा होता, मगर अब तो यह भी नामुमकिन मालूम होता है। आहिस्ता—आहिस्ता मेहनत से पढ़ते जाना। अगर कोई काम सीख सको तो बेहतर होगा, मगर सब कुछ पिता जी की सलाह से करना। जहाँ तक हो सके, मुहब्बत से सब लोग गुजारा करना। इसके सिवाय क्या कहूँ?

जानता हूँ कि आज तुम्हारे दिल के अन्दर गम का सुमद्र ठाठें मार रहा है। भाई तुम्हारी बात सोचकर मेरी आँखों में आँसू आ रहे हैं, मगर क्या किया जाए, हौसला करना। मेरे अजीज, मेरे बहुत-बहुत प्यारे भाई, जिन्दगी बड़ी सख्त है और दुनिया बड़ी बे-मुरव्वत। सब लोग बड़े बेरहम हैं। सिर्फ मुहब्बत और हौसले से ही गुजारा हो सकेगा। कुलतार की तालीम की फिक्र भी तुम ही करना। बड़ी शर्म आती है और अफसोस के सिवाय मैं कर ही क्या

सकता हूँ। साथ वाला ख़त हिन्दी में लिखा हुआ है। ख़त 'के' की बहन को दे देना। अच्छा नमस्कार, अजीज भाई अलविदा.....रुखसत।

तुम्हारा खैर—अंदेश
भगत सिंह

एक पत्र सुखदेव के नाम

(भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज के छात्र थे। एक सुंदर—सी लड़की आते जाते उन्हें देखकर मुस्कुरा देती थी और सिर्फ भगत सिंह की वजह से वह भी क्रांतिकारी दल के करीब आ गयी। जब असेंबली में बम फेंकने की योजना बन रही थी तो भगत सिंह को दल की जरूरत बताकर साथियों ने उन्हें यह ज़िम्मेदारी सौंपने से इंकार कर दिया। भगत सिंह के अंतरंग मित्र सुखदेव ने उन्हें ताना मारा कि तुम मरने से डरते हो और ऐसा उस लड़की की वजह से है। इस आरोप से भगत सिंह का हृदय रो उठा और उन्होंने दोबारा दल की मीटिंग बुलाई और असेंबली में बम फेंकने का जिम्मा जोर देकर अपने नाम करवाया। आठ अप्रैल, 1929 को असेंबली में बम फेंकने से पहले सम्भवतः 5 अप्रैल को दिल्ली के सीताराम बाजार के घर में उन्होंने सुखदेव को यह पत्र लिखा था जिसे शिव वर्मा ने उन तक पहुँचाया। यह 13 अप्रैल को सुखदेव के गिरफ्तारी के वक्त उनके पास से बरामद किया गया और लाहौर षड्यंत्र केस में सबूत के तौर पर पेश किया गया।)

प्रिय भाई,

जब तक तुम्हें यह ख़त मिलेगा, मैं दूर मंजिल की ओर जा चुका होऊँगा। मेरा यकीन कर, आजकल मैं बहुत प्रसन्नचित्त अपने आखिरी सफर के लिए तैयार हूँ। अपनी जिन्दगी की सारी खुशियों और मधुर यादों के बावजूद मेरे दिल में एक बात आज तक चुभती रही। वह यह कि मुझे भाई ने गलत समझा और मुझ पर कमजोरी का बहुत ही गम्भीर आरोप लगाया। आज मैं पहले से कहीं ज्यादा पूरी तरह से सन्तुष्ट हूँ। मैं आज भी महसूस

करता हूँ कि वह बात कुछ भी नहीं, बस गलतफहमी थी। गलत शक था। मेरे खुले व्यवहार के कारण मुझे बातूनी समझा गया और मेरे द्वारा सबकुछ स्वीकार कर लेने को कमजोरी माना गया। लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोई गलतफहमी नहीं, मैं कमजोर नहीं, अपनों में से किसी से भी कमजोर नहीं।

भाई मेरे, मैं साफ दिल से विदा लूँगा और तुम्हारी शंका भी दूर करूँगा। इसमें तुम्हारी बहुत कृपालुता होगी। ध्यान रहे, तुम्हें जल्दबाजी से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सोच—समझकर और शान्ति से काम को आगे बढ़ाना। अवसर पा लेने की जल्दबाजी न करना। जनता के प्रति जो तुम्हारा फर्ज है उसे निभाते हुए काम को सावधानीपूर्वक करते रहना। सलाह के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि शास्त्री मुझे पहले से अधिक अच्छा लग रहा है। मैं उसे सामने लाने की कोशिश करता, बशर्ते कि वह साफगोई से अपनेआप को एक अंधेरे भविष्य के लिए अर्पित करने के लिए सहमत हो। उसे साथियों के नजदीक आने दो ताकि वह उनके आचार—विचार का अध्ययन कर सके। यदि वह अर्पित भाव से काम करेगा तो काफी लाभदायक और मूल्यवान सिद्ध होगा। लेकिन जल्दबाजी न करना।

तुम स्वयं अच्छे पारखी हो। जिस तरह जँचे, देख लेना। आ मेरे भाई, अब हम खुशियाँ मना लें।

खैर, मैं कह सकता हूँ कि बहस के मामले में मुझसे अपने पक्ष पेश किये बिना नहीं रहा जाता। मैं पुरजोर कहता हूँ कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर जीवन की समस्त रंगीनियों से ओतप्रोत हूँ, लेकिन वक्त आने पर मैं सबकुछ कुर्बान कर दूँगा। सही अर्थों में यही बलिदान है। ये वस्तुएँ मनुष्य की राह में कभी भी अवरोध नहीं बन सकतीं, बशर्ते कि वह इन्सान हो। जल्द ही तुम्हें इसका प्रमाण मिल जायेगा। किसी के चरित्र के सन्दर्भ में

विचार करते समय एक बात विचारणीय होनी चाहिए कि क्या प्यार किसी इन्सान के लिए मददगार साबित हुआ है? इसका जवाब मैं आज देता हूँ—हाँ वह मेजिनी था, तुमने अवश्य पढ़ा होगा कि अपने पहले नाकाम विद्रोह,



मन को कुचल डालने वाली हार का दुख और दिवंगत साथियों की याद—यह सब वह बरदाश्त नहीं कर सकता था। वह पागल हो जाता या खुदकशी कर लेता। लेकिन प्रेमिका के एक पत्र से वह दूसरों जितना ही नहीं, बल्कि सबसे अधिक मजबूत हो गया।

जहाँ तक प्यार के नैतिक स्तर का सम्बन्ध है, मैं यह कह सकता हूँ कि यह अपने में एक भावना से अधिक कुछ भी नहीं और यह पशुवृत्ति नहीं बल्कि मधुर मानवीय भावना है। प्यार सदैव मानव चरित्र को ऊँचा करता है, कभी भी नीचा नहीं दिखाता बशर्ते कि प्यार, प्यार हो। इन लड़कियों (प्रेमिकाओं) को कभी भी पागल नहीं कहा जा सकता है जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं—वे सदैव पाशविक वृत्ति के हाथों में खेलती हैं। सच्चा प्यार कभी भी सृजित नहीं किया

जा सकता। यह अपने ही आप आता है—कब, कोई कह नहीं सकता ? प्यार पूर्णतः प्राकृतिक है।

मैं यह कह सकता हूँ कि नौजवान युवक—युवती आपस में प्यार कर सकते हैं और वे अपने प्यार के सहारे अपने आवेगों से ऊपर उठ सकते हैं। अपनी

पवित्रता कायम रखे रह सकते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब मैंने प्यार को मानवीय कमजोरी कहा था तो यह किसी सामान्य व्यक्ति को लेकर नहीं कहा था, जहाँ तक कि बौद्धिक स्तर पर सामान्य व्यक्ति होते हैं पर वह सबसे उच्च आदर्श स्थिति होगी जब मनुष्य प्यार, घृणा और अन्य सभी भावनाओं पर नियन्त्रण पा लेगा। जब मनुष्य तर्क के आधार पर अपना पक्ष अपनायेगा। वर्तमान हालात में जिस तरह लोग प्रेम कर रहे हैं, वह बुरा नहीं बल्कि अच्छा ही है। दूसरे, प्यार की निन्दा करते समय, मैंने एक व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति के प्यार की निन्दा की है, और वह भी एक आदर्शवादी स्थिति

में। लेकिन फिर भी, मनुष्य में प्यार की प्रबलतम भावनाएं होनी चाहिए जिन्हें उसे किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे सर्वव्यापी बना देना चाहिए।

मेरे विचार से मैंने अपने पक्ष को काफी स्पष्ट कर दिया है। हाँ, एक बात मैं तुम्हें खासतौर पर बताना चाहता हूँ कि तमाम रैडिकल विचारों में विश्वास रखने के बावजूद, हम नैतिकता की अति—आदर्शवादी आर्यसमाजी धारणाओं से पीछा नहीं छुड़ा सके हैं। हम तमाम कल्पनीय क्रान्तिकारी चीजों के बारे में लम्बी—चौड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में सामना होते ही हम थर—थर काँपना शुरू कर देते हैं।

मैं तुमसे अर्ज करूँगा कि यह कमजोरी त्याग दो। अपने मन में बिना कोई गलत भावना लाये अत्यन्त नम्रतापूर्वक क्या

मैं तुमसे आग्रह कर सकता हूँ कि तुममें जो अति आदर्शवाद है उसे थोड़ा—सा कम कर दो। जो पीछे रहेंगे और मेरी जैसी बीमारी का शिकार होंगे, उनसे बेरुखी का व्यवहार न करना, झिड़ककर उनके दुख—दर्दों को न बढ़ाना, क्योंकि उनको तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत

जहाँ तक प्यार के नैतिक स्तर का सम्बन्ध है, मैं यह कह सकता हूँ कि यह अपने में एक भावना से अधिक कुछ भी नहीं और यह पशुवृत्ति नहीं बल्कि मधुर मानवीय भावना है। प्यार सदैव मानव चरित्र को ऊँचा करता है, कभी भी नीचा नहीं दिखाता बशर्ते कि प्यार प्यार हो। इन लड़कियों (प्रेमिकाओं) को कभी भी पागल नहीं कहा जा सकता है जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं—वे सदैव पाशविक वृत्ति के हाथों में खेलती हैं। सच्चा प्यार कभी भी सृजित नहीं किया जा सकता। यह अपने ही आप आता है -कब, कोई कह नहीं सकता ?

प्यार पूर्णतः प्राकृतिक है।

है। क्या मैं यह आशा रखूँ कि तुम किसी विशेष व्यक्ति के प्रति खुन्दक रखने के बजाय उनसे हमदर्दी रखोगे, उनको इसकी बहुत जरूरत है। तुम तब तक इन बातों को नहीं समझ सकते जब तक कि स्वयं इस चीज का शिकार न बनो। लेकिन मैं यह सब कुछ क्यों लिख रहा हूँ? दरअसल मैं अपनी बातें स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। मैंने अपना दिल खोल दिया है।

तुम्हारी सफलताओं और जीवन के लिए शुभकामनाओं के साथ।

तुम्हारा,
भगत सिंह



पूर्वी दिल्ली के दो स्कूलों को स्विमिंग पूल का तोहफ़ा

पूर्वी दिल्ली के दो सरकारी स्कूलों के बच्चों की बरसों पुरानी मुराद पूरी हो गई। 7 अप्रैल का दिन उनके लिए खास बन गया। इन स्कूलों को दिल्ली सरकार ने स्विमिंग पूल का तोहफा देकर, उनके सपनों को पंख लगा दिए। जिन बच्चों को तैरना नहीं आता उनके मन में भी तैराक बनने का सपना उग आया। गर्मी में बच्चों के सामने स्वच्छ पानी से लहराता तरणताल कैसा आनंद भरता है, यह समझने के लिए बच्चों जैसा मन चाहिए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मयूर विहार फेज-2 और ईस्ट विनोद नगर के स्कूलों में बने इन दोनों स्विमिंग पूलों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये पूल स्कूल के समय में स्कूल के बच्चों के लिए खुले रहेंगे लेकिन इसके बाद दूसरे सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चे भी यहाँ तैराकी सीख सकेंगे। मयूर विहार फेज-2 के पॉकेट-बी में एनी बेसेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय और



वेस्ट विनोद नगर में राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में ये स्विमिंग पूल बने हैं।

अखबारों में यह ख़बर प्रमुखता से छपी। नवभारत टाइम्स में छपी ख़बर में बताया गया कि विनोद नगर के स्कूल की पांचवीं की स्टूडेंट पूजा जोशी कहती हैं, 'मुझे तैरना नहीं आता। मैंने बहुत पहले घर में कहा था कि जैसे ही पूल बनेगा मैं तैरना सीखूंगी। अब मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि कब से ट्रेनिंग शुरू होगी।' स्विमिंग में स्कूल की ओर से नैशनल लेवल तक पहुंच चुके 12वीं के केविन बताते हैं कि अभी वह झंडेवालान के सरकारी स्कूल में तैराकी के लिए जाते हैं, और अब यहां तैराकी करेंगे। वह क्लास 6 से पूल का इंतजार कर रहे हैं।

झंडेवालान के स्कूल में ट्रेनिंग लेने वाले कुछ छात्रों ने इस अवसर पर तैराकी का कमाल दिखाया। इस साल के स्कूल नैशनल्स में तीन गोल्ड मेडल जीतने वाली भव्या सचदेवा कहती हैं, 'यह पूल वर्ल्ड क्लास का है और जो बच्चे स्विमर या चैंपियन बनना चाहते हैं, वे यहां रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरह ट्रेनिंग ली थी।'

झंडेवालान में ट्रेनर इंटरनैशनल तैराक एडना शर्मा कहती हैं, 'पिछले 3 साल से हम स्कूल नैशनल्स में चैंपियन हैं और दिल्ली का तैराकी का लेवल ऊपर हुआ है। अभी 17 सरकारी स्कूलों में पूल हैं। यानी बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का बढ़िया मौका है।'

ईस्ट विनोद के स्कूल में सीएम केजरीवाल ने कहा, 'सरकारी स्कूलों के बच्चों के अंदर मैं अब गजब का कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ। कई सालों से यह सोच थी कि सरकारी स्कूल नहीं बदल सकते मगर सरकार ने दिखा दिया कि आप ईमानदार हैं तो सरकारी स्कूल भी बदल सकते हैं। पिछले साल तो हमारे 350 बच्चों ने आईआईटी में एडमिशन पाया है। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली ने नया मॉडल दिया है।

शिक्षा विभाग की कमान सम्भाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इन पूलों को असली स्विमिंग पूल तो बच्चे ही बनाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने प्रधानाचार्य और शिक्षकों से अपील की कि बच्चों का जोश तैराकी के लिए भी बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा न हो मगर वह अच्छा तैराक बन जाए और शायद उसका मन मैथ्स में भी लगने लगे। बच्चे को यह बिल्कुल न कहें कि स्विमिंग में टाइम बर्बाद मत करो। उन्होंने कहा कि बच्चों की शख्सियत का विकास करने के लिए सरकार हर आयाम पर ध्यान दे रही है। ■





शिक्षा की बुनियाद मज़बूत करने
को शुरू हुआ मिशन बुनियाद

पढ़ने में कमज़ोर बच्चे शिक्षा व्यवस्था की असफलता-सिसोदिया

दिल्ली में शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने के लिए सरकार ने 'मिशन बुनियाद' की शुरुआत कर दी है। इसके तहत कक्षा तीन से नौ तक के सभी बच्चों को तीन महीने के अंदर पढ़ने-लिखने और सामान्य गणित में सक्षम बनाया जाएगा। इस मिशन में केवल सरकार के अपने स्कूल नहीं, एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कैंट बोर्ड के स्कूलों के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा।

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 11 अप्रैल को इस महात्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत करते हुए शिक्षाविभाग की कमान संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 'मिशन बुनियाद' को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसे सकारात्मक रूप से पूरा करने की जरूरत पर बल दिया क्योंकि अभिभावकों और बच्चों में यह हीन भावना आ रही है कि पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से वे इसका हिस्सा हैं। उन्होंने सभा में मौजूद शिक्षा विभाग के अधिकारियों, स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों से कहा कि हीन भावना के साथ मिशन की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। इसे सकारात्मक बनाना जरूरी है।

श्री सिसोदिया ने कहा कि अगर पांच साल स्कूल जाने के बाद भी बच्चे को पढ़ना-लिखना नहीं आ रहा है तो इसमें पूरा एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है। बच्चे को दोष देना गलत है। गौरतलब

है कि कई सर्वेक्षणों में यह बात सामने आई थी कि स्कूल जाने वाले बच्चों का एक हिस्सा ऐसा भी है जो पढ़-लिख भी नहीं सकता ऐसे बच्चे क्लास के साथ नहीं चल पाते। शिक्षकों और बाकी बच्चों को भी काफी परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले साल जगह-जगह रीडिंग क्लास चलवाई थी। कक्षा 3, 5 और 8 के बच्चों के स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने इस बार 'मिशन बुनियाद' को एक अभियान की शक्ल में पेश किया है। अभियान के तहत स्कूली छुट्टियों के दौरान बच्चों को पढ़ाया जायेगा। यह अभियान जून तक चलेगा। इस अभियान के लिए सरकार रेडियो के जरिए अभिभावकों से अपील कर रही है कि वे इस दौरान दिल्ली रहकर बच्चों को एक्टिविटी पर आधारित क्लासों में भेजें। बच्चों को रोज 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग देकर एक्सपर्ट बनाया जाएगा।

यह मिशन बच्चों की नींव को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। भाषायी ज्ञान हो या गणित का गुणा-भाग सभी की जानकारी और सभी विषयों में मजबूत बनाने पर जोर होगा। सरकार ने शिक्षकों को इस मिशन की ट्रेनिंग देने के लिए मैनुअल भी जारी कर दिया है जिसमें सरकार ने अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाने के सभी तकनीकी जानकारीयां मुहैया कराई हैं। शिक्षक बच्चों के अभिभावकों को इस मिशन की जानकारी देगा और स्कूल प्रशासन भी परिजनों को संदेश भेजकर बच्चों को कैम्प में भेजने का अनुरोध भी करेंगे। ■



ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 53000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਬਜਟ’ ਦਾ ਆਕਸੀਜ਼ਨ !

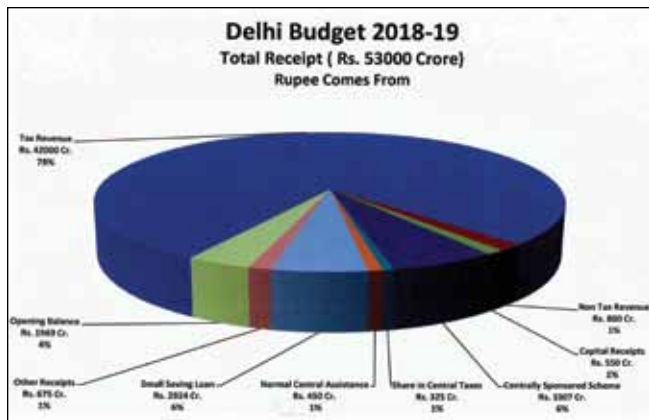
23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ 2018-19 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਭਵਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਲ 53000 ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪਰਿਆਵਰਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 26 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ-ਡਾਊਨ’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ-ਅਪ-ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ‘ਟ੍ਰਿਕਲ-ਅਪ-ਇਕੋਨੋਮੀ’ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇ, ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਵਧੇ। ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਨਾਅਰਾ ਹੈ - ‘ਸਿੱਖਿਅਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਵਸਥ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਮਰੱਥ ਰਾਸ਼ਟਰ’।

DELHI BUDGET 2018

ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੌਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ

ਬਜਟ ਲਗਭਗ ਦੋ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਦਾ ਬਜਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚ - 15.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਪਾਲੀਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸਵਾਸਥ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਸ ਤੇ ਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਸਥ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 11.3 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਔਸਤ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

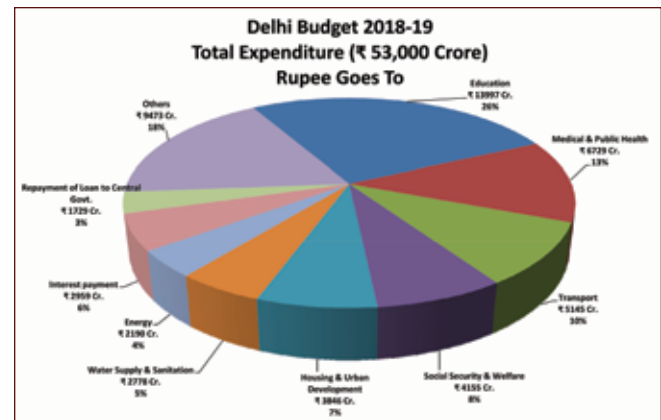


ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਪੀਣ ਦਾ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਸੀਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਕਲ-ਅਪ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼

ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੌਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਕਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤਮਾਨ ਰੇਟਾਂ ਤੇ, ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2017-18 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 6.86,017 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੋ 2016-17 ਵਿਚ 6,16,826 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 11.22 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਸੰਧਰਭ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 8.14 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਦਰ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਾਧਾ 2015-16 ਤੋਂ 2017-18 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 2011-12 ਦੇ 3.94



ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿਚ 4.10 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਕੇਵਲ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਗ੍ਰੋਸ-ਸਟੇਟ-ਵੈਲਯੂ-ਅਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 85.92 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 12.04 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਧਿਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਤੇ 2.04 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁਲਾਂ ਤੇ 2017-18 ਵਿਚ ਵਧੇ ਕੇ 3,29,093 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 2016-17 ਵਿਚ 3,00,793 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017-18 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 9.41 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ

1,21,764 ਰੁਪੈ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2.92 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਨ ਬਜਟ

ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਟ-ਆਊਟਕਮਸ ਯਾਨੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਊਟਕਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟਕਮ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ-ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ 'ਵਰਲਡ ਰਿਸੋਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ' ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਤਸਰਜਨ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਤ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਰਾਜ ਬਣੇਗਾ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਰਿਯਲ-ਟਾਈਮ-ਡੇਟਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੀ-40 ਸਿਟੀਜ਼-ਫਾਰ-ਕਲਾਈਮੇਟ-ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਗ੍ਰੀਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਿਭਾਗ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ 5.5 ਲਖ ਪੌਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਤਕ ਤਿੰਨ ਲਖ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਏਂਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 7.93 ਲਖ ਛੋਟੇ ਦਰਖਤ-ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਲਖ ਪੌਦੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਆਂਗਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ

ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਰਿਤ ਖੇਤਰ 2015 ਵਿਚ 299.77 ਵਰਗ

ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017 ਵਿਚ 305.41 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡਰਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਖਾਂ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਏਅਰ-ਅੰਬੀਐਂਸ-ਫੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਵਿਲਾਇਤੀ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਏ ਰਖਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਈਥਣ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਈਪਡ ਨੋਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਲਖ ਰੁਪੈ ਤਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੇਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਇਲਾ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਗੈਸ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਤੰਦੂਰ ਤਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਤੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ 10 ਕੇਵੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਡੀਜਲ ਜਨਰੇਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੱਛ ਈਥਣ ਤੇ ਆਧਾਰਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਨਰੇਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਤਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਪਾਲ ਚੌਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼



DELHI BUDGET 2018

ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲੇਵਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ

ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਡੋਰ ਡਿਸਪਲੇ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਕ ਮਾਡਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਚਾਨਕ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ

ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਬਸ ਸਮੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਬਸ ਥੇੜੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਫਾਯੂਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਸਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ-ਮਾਈਲ-ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਦੇ ਥੇੜੇ ਵਿਚ 905 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਡਰ ਵਹੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਭਲੇ

ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰ-ਅੰਬੀਯੰਸ-ਫੰਡ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਐਸ-2 ਅਤੇ ਬੀਐਸ-3 ਦੋਪਹੀਆ, ਵਾਹਨਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੁਡਸ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਜੀ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਂਟ੍ਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਐਨਜੀ-ਫੈਕਟਰੀ-ਫਿਟੇਡ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜੇਜ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਓਵਰਲੋਡ ਟ੍ਰਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾੜੀ, ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਸਥਿਤ ਇੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਪਿਟਸ ਤੇ ਵੇਇੰਗ-ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ 60 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ, ਬਾਡੀ-ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਈ-ਚਾਲਾਨਿੰਗ ਟੈਬ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਯੂਸ਼ਨ-ਅੰਡਰ-ਕੰਟਰੋਲ (ਪੀਯੂਸੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਸੇਂਟਸਰਸ ਦਾ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ-ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਐਮਆਈਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਡਣ ਵਾਲੀ ਮਿਟੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਉਡੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-

ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਸ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਕੋ ਮਾਡਲ ਦੇ





ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਕ ਪਾਈਲੈਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਕਿ.ਮੀ. ਲੰਬੇ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਊਰਜਾ

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਮਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਓਵਰ-ਆਲ ਇਕੋਨੋਮੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 37.28 ਲਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ 82.84 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 1,720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਨੂਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਐਸੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਸਿਲ-ਫਯੂਲ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁਲ ਰਿਨੂਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਮਰਥਾ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤਕ 133.13 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 81.13 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 52 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਸੰਯੋਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 74 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸੰਵਰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸਰਜਨ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ

ਇਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੌਰ

ਊਰਜਾ ਨੈਟ ਮੀਟਰ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸੰਯੋਗਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਗਰੁਪ-ਨੈਟ-ਮੀਟਰਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੁਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਯਲਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਗ੍ਰੀਕਲਚਰ-ਕਮ-ਸੋਲਰ-ਫਾਰਮ-ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੁਕ ਕੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ-ਬਾਡੀ ਵਿਚ ਲਗੇ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਅਫਿਸ਼ੀਏਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਦਫਤਰਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰੇ ਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਘਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (ਈਸੀਬੀਸੀ)



DELHI BUDGET 2018

ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਡ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ 500

ਵਰਗਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਿਵਹਨ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪਰਿਵਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ 41,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

2017-18 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਕੇ 10,000 ਨਵੇਂ ਆਟੋ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8,600 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਆਟੋਮੋਟਿਡ ਕ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਸਜੂਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਭਾਗਿਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2018-19 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂਚਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਫਟ

ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ 1,000 ਬਸਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਖੁਦ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਲਸਟਰ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਟੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਯੋਗਿਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਡੀਟੀਸੀ ਦੀਆਂ 200 ਅਤੇ 50 ਕਲਸਟਰ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਟੀਐਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਡੀਟੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਸਾਂ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 7 ਬਸ ਡਿਊ - ਢਿਚਾਓ ਕਲਾਂ-2, ਬਵਾਨਾ ਸੈਕਟਰ-1, ਰੇਵਲਾ ਖਾਨਪੁਰ, ਰਾਣੀ ਖੇੜਾ-1, ਰਾਣੀ ਖੇੜਾ-2, ਰਾਣੀ ਖੇੜਾ-3 ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਖਰਖਰੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬਸ ਡਿਊ ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 6 ਨਵੇਂ ਬਸ ਡਿਊ ਘੁੰਮਨ ਹੇੜਾ, ਮੁੰਡੋਲਾ ਕਲਾਂ, ਰੋਹਿਣੀ ਸੈਕਟਰ-37, ਈਸਟ ਵਿਨੋਦ ਨਗਰ, ਬਵਾਨਾ ਸੈਕਟਰ-5 ਅਤੇ ਵੀਆਈਯੂ ਬੁਰਾੜੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪਰਿਵਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਡੀਟੀਸੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ 24 ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ 85 ਬਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ 38 ਬਸਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਡੀਟੀਸੀ, ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਡੀਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਵਿਚ 2,370 ਸਿਵਿਲ ਡਿਫੇਂਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ 120 ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿਸੇ ਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਭਵਨ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ,





ਸਾਫ਼ ਸ਼ੋਚਾਲਯ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਧਰਭ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਆਦਿ ਐਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ - ਹੈਪੀਨੇਸ ਕਰਿਕੁਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਜਮਾਤ 8 ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਐਸੇ ਘਟਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ

ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਰਜ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ

ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਐਸਾ ਪੱਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਸਥ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਐਸਐਮਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਐਮਸੀ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਸਐਮਸੀ ਨੂੰ 5 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਚਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਐਮਸੀ ਸਾਰਟ-ਟਰਮ-ਬੋਸਿਸ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪਰਸਨ ਰਖ ਪਾਏਗੀ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਆਰਟ, ਡਾਂਸ, ਆਈਆਈਟੀ-ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਕਲਾਸ ਕਰਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਐਸਐਮਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਪੀਟੀਐਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਯਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰੋਂਟਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਸੰਧਰਭ ਵਿਚ ਸਟੂਡੈਂਟ-ਟੀਚਰ ਅਨੁਭਾਗ ਬਣਾਏ ਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 12,748 ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, 30 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ 366 ਸਰਵੋਦਯ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 155 ਸਰਵੋਦਯ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 144 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਣਿਜ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਟਬੁਕ ਪੜ੍ਹਨ

DELHI BUDGET 2018

ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਸਕਿਲ ਡੇ ਵਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਚੁਣੌਤੀ 2018' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਮਾਤ 1 ਤੋਂ 8 ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਥ ਸਕਿਲਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1.2 ਲਖ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਭਵਨ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ 200 ਤਕ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਗਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਰਿਜਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੇਬਲੇਟ (ਟੈਬ) ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਰਿਜਲਟ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਦਿ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਭੇ

ਜਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਇਸ ਟੈਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਡਰਨ ਸਟਾਫ਼ ਰੂਮ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਠਿਨ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏ ਰਖਣ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਿੱਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਅਲਗ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਸਥ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੂਚੀ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਕੈਂਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2000 ਰੁਪੈ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਟਾਪ ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 426 ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗੇ, 205 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 169 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ -“ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ” ਅਤੇ “ਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ” ਯਾਨੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ। “ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਐਸੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਕਿੰਗ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਟਾਪ ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵਧ



ਚੜ੍ਹਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। “ਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਥਾਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਖ-ਵਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ-ਕੁਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 2018-19 ਵਿਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ-ਆਈਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਦੂਜਾ

ਪੜਾਅ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਈਆਈਆਈਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਕਾਲਜ ਆਫ ਬਿਜਨੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ 132.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਡੀਟੀਯੂ ਦਾ ਪੂਰਵੀ ਕੈਂਪਸ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 300 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡੀਟੀਯੂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 2014-15 ਵਿਚ 2,564 ਸੀ, ਉਹ 2017-18 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 3,689 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਧੀਰਪੁਰ ਵਿਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ 2018-19 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੂਰਵੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਰਜਮਲ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀਜੀਐਸਆਈਪੀਯੂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 2017-

18 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 34,094 ਹੋ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੂਰਵੀ ਪਰਿਸਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ

2017-18 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਨਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਕਿ ਆਈਟੀਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 25 ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 25,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਹਾਇਰ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਅਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਨਾਂ



ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਨਾਤਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ “ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟਯੂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਯੂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ (50 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2.50 ਲਖ ਰੁਪਏ

DELHI BUDGET 2018

ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ 6 ਲਖ ਰੁਪੈ ਤਕ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ

ਟਯੂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 10ਵੀਂ/12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲੋਨ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ, ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਰਾਈਵਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 20 ਲਖ ਆਕਰਾਈਵਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ 2018-19 ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ 13 ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਅਤੇ ਅਭਿਲੇਖ ਵਿਚ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਵਾਸਥ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 3 ਪੱਧਰੀ ਸਵਾਸਥ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਪੋਲੀਕਲਿਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਵਾਸਥ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ 164 ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ



ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਰੀਬ 80 ਲਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ 530 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਕਸ਼ 1,000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 24 ਪਾਲੀਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 94 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਐਸੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਵਾਸਥ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਵਿਚ 600 ਬਿਸਤਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬੁਰਾੜੀ ਵਿਚ 800 ਬਿਸਤਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਵਾਰਕਾ ਵਿਚ 1,500 ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 2,546 ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਈਪੁਰ, ਜਵਾਲਾਹੇ ਝੀ, ਹਸਤਸਾਲ, ਸਰਿਤਾ ਵਿਹਾਰ, ਦੀਨਦਾਰਪੁਰ, ਕੇਸ਼ਪੁਰਮ, ਅਤੇ ਛਤਰਪੁਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਡਾਯਗਨੋਸਟਿਕ-ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਸਥ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਸੀਟੀ, ਪੀਈਟੀਸੀਟੀ, ਰੇਡੀਓ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਕੈਨ, ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ, ਕਲਰ ਡੋਪਲਰ, ਇਕੋ, ਟੀਐਮਟੀ, ਈਈਜੀ ਅਤੇ ਈਐਮਜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਰੇਡੀਓਲਾਜੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਐਸਿਡ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਜਾਂ ਤਪਨ ਨਾਲ ਸੜੇ ਜਖਮੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਲੇ ਹੀ ਐਸੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ

ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 24 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ “ਪਹਿਲਾ ਮਦਦਗਾਰ ਵਾਹਨ” ਰਿਸਪਾਂਡਰ ਵਹੀਕਲ (ਐਫਆਰਵੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਫਸਟ ਐਥੂਲੈਂਸ ਕਾਰਮਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ 16 ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਨ ਸਵਾਸਥ ਕੇਂਦਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਡ ਪੀਯੂਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਵੁਸ ਦੀ ਉਪ-ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਵਾਸਥ ਸਮਿਤੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਾਸਥ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਮੂਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਵਾਸਥ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਖ ਅਤੇ ਕੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਉਪਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਸਥ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ

ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰੀਬ 7 ਲਖ ਲਾਭਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਮੁਸ਼ੀਬਤਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 10,897 ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 12 ਲਖ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਪੂਰਵ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ “ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਉਨਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਜ਼, ਕੁਰਸੀ, ਚਟਾਈਆਂ, ਖਿਡੌਣੇ ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਡਲ ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਅਰਲੀ-ਚਾਈਲਡਹੁਡ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ” ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ/ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ “ਲਾਡਲੀ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੇਂਜਿਟ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਜੈ ਭੀਮ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਯੋਜਨਾ” ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਜਾਂ ਕਲਾਸ 12 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਨਿਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ



ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲਖ ਰੁਪੈ ਤਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 6 ਲਖ ਰੁਪੈ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੂਰਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ



ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਮੁਦਾਏ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰ

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਆਊਟਕਮ ਬਜਟ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ, ਨਾਨ ਰਿਵੇਨਯੂ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਲਕਾ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕਿਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੂਜ਼ੀਆਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਪਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਲਕਾ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਵੇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੀਵੇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 450 ਐਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 89 ਐਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਅਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 361 ਐਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਵਹਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਬਾਗਵਾਨੀ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰਸ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੀਵੇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਐਸਟੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਚ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਰਾੜੀ, ਛਤਰਪੁਰ, ਕਿਰਾੜੀ, ਨਰੇਲਾ, ਜੀਦਪੁਰ, ਪੱਲਾ, ਬਵਾਨਾ, ਕੰਡਾਵਲਾ, ਬਦਰਪੁਰ, ਮੁੰਡਕਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਕ ਸਮਰਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ 162 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਰੀਫੇਰਿਯਲ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਟ੍ਰੈਂਚਲੈਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨਕਾਲ 50 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

ਸਰਕਾਰ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ



ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੀਐਸਆਈਡੀਸੀ, ਆਈ ਐਂਡ ਐਫਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਮ ਅਤੇ ਜੇਜੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਨੀਤੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੁੱਗੀ ਝੱਪੜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਉਸੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2017-18 ਦੌਰਾਨ 1,600 ਜੇਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਅਤੇ ਬਾਪਰੋਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝੁੱਗੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ੌਚਾਲਯਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 16,000 ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਚਾਲਯਾਂ ਪਰਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੜਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤਕ ਅਲੇਵੇਟੇਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਾਪੁਲਾ ਨਾਲਾ (ਪੜਾਅ-2) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਮਯੂਰ ਵਿਹਾਰ ਤਕ ਬਾਰਾਪੁਲਾ ਨਾਲਾ (ਪੜਾਅ 3) ਦੇ ਅਲੇਵੇਟੇਡ ਰੋਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤੇ 1260 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਲੇਵੇਟੇਡ ਰੋਡ ਬਣਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 10-12 ਮਿੰਟ ਘਟ ਲਗਣਗੇ ਜਦ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਕਰੋਲਾ ਮੋੜ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤਕ ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ ਨਾਲੇ

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਲੇਵੇਟੇਡ ਰੋਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਈਟੀਪੀਓ ਤੋਂ ਭੈਰੋਂ ਰੋਡ-ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 700 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਨਹਿਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲਿੰਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਵੀ 2018-19 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਬਾਈਪਾਸ ਤਕ ਅਲੇਵੇਟੇਡ ਰੋਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਵੀ 2018-19 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਡੀਐਨਡੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਵਿਚ ਰਿੰਗਰੋਡ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਘਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 20-30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਨਆਈਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ





ਹਾਈਟੈਕ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ-ਸਮਾਰਟ ਕ੍ਰਿਸੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਈ-ਬਸਾਂ ਚਲਣ ਲਗਣਗੀਆਂ। 1000 ਨਵੀਆਂ ਡੀਟੀਸੀ ਬਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 11 ਮਈ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਬਿਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਡ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਬਿਡ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਵਰਕ-ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। 20 ਨਵੰਬਰ ਤਕ 40 ਬਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੋਪ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 120 ਬਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 960 ਬਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਨਵੀਆਂ ਕਲਸਟਰ ਬਸਾਂ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿਡਸ ਅਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਬਿਡਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਈ ਤਕ ਲੇਟਰ ਆਫ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿਚ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਸੈਕਟਰਸ ਵਿਚ 251 ਬਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ 749 ਬਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਵਾਸਥ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 530 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ 230 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਕਲੀਨਿਕ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਸਥ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਸਪੀਟਲ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਐਚਆਈਐਮਐਸ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਐਚਆਈਐਮਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਐਫਪੀ 30 ਜੂਨ 2018 ਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਤਕ ਐਵਾਰਡ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਯਲ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪਰਚੇਜ ਆਦਿ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ-ਸਟੋਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿਡਿੰਗ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਬਿਡ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ 1 ਮਈ 2018 ਤਕ ਚੁਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 15 ਜੂਨ, 2018 ਤਕ ਐਵਾਰਡ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਕੰਮ 15 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 22 ਮਈ 2018 ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਮੋਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋੜਾ ਸਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਧੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਰ-ਸਟੋਪ-ਡਿਲਿਵਰੀ-ਆਫ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ■



مختلف سرکاری خدمات کی ڈور اسٹیپ ڈیلیوری کی بھی ٹائم لمٹ طے کر لی گئی ہے۔ سٹڈر کی جانچ، کلینیکل بڈس و فنانشیل بڈ وغیرہ کا کام اپریل مہینے میں پورا کرکیم مئی 2018 تک منتخب کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر لیا جائے گا اور 15 جون 2018 سے یہ مہم لاگو ہو جائے گی۔ سرکاری اسکولوں میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کے پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے اس کا سٹڈر 15 جون 2018 تک اوارڈ کر دیا جائے گا پروجیکٹ کا کام 15 جولائی 2018 کو شروع ہونے اور جنوری 2019 کے آخر تک پورا ہو جانے کا تخمینہ ہے۔ اس سے پہلے اس پروجیکٹ کا سات اپریل 2018 تک ابتدائی تخمینہ جمع کرنے اور 22 مئی 2018 تک انتظامی منظوری و خرچ منظوری ادا کرنے کا امکان ہے۔

غریبوں کو راشن دینے کی مہم ملک میں کافی مشہور ہے لیکن اس کے بارے میں کٹوا سچ یہ بھی ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ چوری میں چلا جاتا ہے۔ دہلی سرکار ایک انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے غریب لوگوں کو دیا جانے والا راشن سیدھے ان کے گھر پہنچانے کی مہم لے کر آرہی ہے۔ ڈور اسٹیپ ڈیلیوری آف راشن نام کی اس مہم سے غریب لوگوں کے راشن کی چوری رُکے گی، ان کو فائدہ ہوگا۔ ■



کر لئے جائیں گے۔ اس کے بعد بڈ کھولنا، فنانشیل بڈ وغیرہ کی عمل پورا کرتے ہوئے 20 جولائی تک ورک آؤر جاری کر دئے جائیں گے، 20 نومبر تک چالیس بسوں کی پہلی قسط آجائے گی اور اس کے بعد 120 بسیں مینے کی بنیاد پر اگلے آٹھ مہینوں میں 960 بسیں دہلی کی سڑکوں پر آجائے گی۔

اسی طرح ایک ہزار نئی کلسٹر بسیں بھی جوڑنے کی ٹائم لمٹ بھی سرکار نے طے کر لی ہے اس کی ٹیکنیکل بڈس ابھی جمع ہو رہی ہیں۔ 6 اپریل تک فنانشیل بڈس کھول لی جائیں گی اور 30 اپریل تک کا بینہ سے منظوری لیکر 31 مئی تک لیٹر آف اوارڈ جاری کر دیا جائے گا۔ ستمبر 2018 سے نومبر 2018 کے بیچ الگ الگ سیکٹرز میں 251 بسیں اور اس کے بعد دسمبر 2018 سے فروری 2019 کے بیچ باقی 749 بسیں دہلی کی سڑکوں پر آجائیں گی۔

صحت کے حلقہ میں سب سے ضروری پروجیکٹ محلہ کلینک بنانے کی ٹائم لمٹ طے کر لی گئی ہیں۔ 530 محلہ کلینک و 230 اسکولوں میں اسکول کلینک بنانے کا کام 30 اکتوبر 2018 تک پورا کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلے چار مہینوں میں اس میں اسٹاف کی تقرری کر سبھی محلہ کلینکس کو چالو کر دیا جائے گا۔ صحت حلقہ کی ایک اور ضروری مہم ہاسپٹل انفارمیشن منیجمنٹ سسٹم یعنی ایچ آئی ایم ایس بنانے کی ہے۔ ایچ آئی ایم ایس لاگو کرنے کیلئے آر ایف پی 30 جون 2018 تک جاری کر دی جائے گی۔ اس کا سٹڈر 30 ستمبر 2018 تک اوارڈ کر دیا جائے گا پوری دہلی کیلئے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرنے کے کام میں قریب چھ مہینے لگیں گے اس کے بعد ٹریننگ، ٹرائل، ہارڈ ویئر پر چیز وغیرہ پورا کر اس مہم کو 1 جولائی 2019 سے لاگو کیا جائیگا۔

DELHI BUDGET 2018

یمنا اور آگرہ نہر کے ساتھ
ساتھ ڈی این ڈی فلائی اوو
اور فرید آباد کے بیج کالندری

بائی پاس کا تعمیراتی کام بھی 2018-19 میں شروع کر دیا
جائے گا۔ سکینر برج سے کالندری کنج بائی پاس تک ایلوئیڈ روڈ
کی تعمیر کا کام بھی 2018-19 میں شروع ہو جائے گا۔ اس سے
وزیر آباد روڈ اور ڈی این ڈی فلائی اوو کے بیچ رنگ روڈ پٹرئیٹک
کم ہوگا۔ اس پروجیکٹ کے پورا ہونے کے بعد اس راستے پر سفر
کے وقت میں بیس سے تیس منٹ کی کمی آئے گی۔

سرکار نے دہلی میں وائی فائی کی سہولت مہیا کرانے کیلئے عزم
جتایا ہے۔ وائی فائی سہولت کو جلدی مہیا کرانے کیلئے یہ پروجیکٹ
آئی ٹی محکمہ سے لیکر لوک زمان و بھاگ کو سونپا گیا ہے اس کیلئے
بجٹ میں سو کروڑ روپے کا انتظام کیا گیا ہے۔

ترقی

دہلی کے سبھی گاؤں کے چو طرف ترقی کیلئے دہلی گرام وکاس بورڈ کی
تشکیل کی گئی ہے۔ عزت مآب ایم ایل اے اپنی گرام وکاس پرو
جیکٹوں کی حالت کے بارے میں آن لائن جانکاری حاصل کر سکیں
اس کیلئے این آئی سی کی مدد سے ایک ایپ تیار کیا جائے گا۔
سرکار دہلی کے دیہاتی علاقوں میں ہائی ٹیک ڈیمونسٹریشن
فارموں کی ترقی کیلئے ایک نئی اسکیم اسمارٹ زراعتی اسکیم لاگو کرے
گی ان سے کسان پیداوار بڑھانے کیلئے تیار کی گئی نئی تکنیکوں اور
فصلوں کی قسموں کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکے گی اور ان
کا استعمال کر سکیں گے۔

دہلی میں اگلے مارچ یعنی مارچ 2019 سے سڑکوں پر ای
بیس چلنے لگیں گی۔ ایک ہزار نئی ڈی ٹی سی بسیں خریدنے کا ٹائم
لمٹ بھی سرکار نے طے کر لی ہے۔ گیارہ مئی تک اس کے بڈجٹ جمع

جے جے خاندانوں کو دو رکاوٹ اور باپروہ میں منتقل کیا گیا۔
جھنگی باشندوں کیلئے قریبی اچھی طرح برقرار اور محفوظ بیت الخلاء کے
استعمال کا انتظام کیلئے پچھلے تین سالوں میں قریب 16000 بیت
الخلاء سیٹوں کی تجدید کاری یا تعمیر کی گئی۔ یکم جنوری 2018 سے ان
بیت الخلاء پر یسروں کو مسلم باشندوں کیلئے مفت دن رات استعمال کیلئے
مہیا کرایا گیا ہے۔

سڑک و دوسرے بنیادی ڈھانچہ

پچھلے دنوں باہری رنگ روڈ پر وکاس پوری سے وزیر آباد تک
ایلوئیڈ کوریڈو کو سکنل فری کیا جا چکا ہے۔ اس سے وکاس پوری سے
وزیر آباد تک سفر کے وقت میں لگ بھگ 45 منٹ کی بچت ہو رہی ہے
بارہ پولا نالہ (دوسرا مرحلہ) کی تعمیر کا کام مارچ 2018 تک پورا ہو
نے کی امید ہے۔ اس سے رنگ روڈ پر گاڑیوں کی بھیڑ بھاڑ سے نجات
ملے گی اور سفر کے وقت میں 15 سے 20 منٹ کی بچت ہوگی۔ سرائے
کالے خان سے میروہار تک بارہ پولا نالہ (تیسرا مرحلہ) کے ایلوئیڈ
روڈ کا تعمیراتی کام دسمبر 2018 تک پورا کر لیا جائے گا۔ اس پرو
جیکٹ پر بارہ سے 60 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی یہ ایلوئیڈ روڈ
بننے سے سفر کے وقت میں دس بارہ منٹ کم لگیں گے جب کہ اس میں
ابھی آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ کمرولہ موڑ سے وزیر آباد تک نجف گڑھ نالے
کے ساتھ ساتھ ایلوئیڈ روڈ کی تعمیر کا کام 2018-19 کے دوران
شروع کر دیا جائے گا۔

آئی ٹی پی او سے بھیروں روڈ۔ رنگ روڈ جنکشن سے پرانا قلع روڈ
کے نیچے سات سو میٹر لمبی سرنگ کی تعمیر کا کام پیش رفت پر ہے۔ اس
پروجیکٹ کے پورا ہونے کے بعد انڈیا گیٹ سے رنگ روڈ پہنچنا
آسان ہو جائے گا اور سفر کے وقت میں دس پندرہ منٹ تک کی کمی
آئے گی۔



پانی کو پینے میں استعمال نہیں کیا جاسکتا لیکن دہلی کو ہر-بھرا بنانے کیلئے سڑکوں کے کنارے اور پارکوں میں باغبانی، ورکشاپ، انڈسٹریل کولنگ ٹاورس وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

اب سرکار پوری دہلی میں چھوٹے چھوٹے سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے گی۔ جیسے ایک کالونی میں چھوٹا ایس ٹی پی لگایا جائے گا اس سے نکلنے والے صاف پانی کو وہیں لوگوں کے گھروں میں حاجت پوری وغیرہ کیلئے، اس علاقے میں ہریالی کیلئے اور کسی واٹر باڈی میں استعمال کیا جائے گا۔ براڑی، چھتر پور، کراڑی، نریلا، جند پور، پلا، بوانہ، کنجھاولا، بدر پور، منڈکا اور نجف گڑھ کی مختلف کالونیوں میں یہ پروجیکٹس لگائے جائیں گے۔

سیور لائنوں کی کیریئر کی صلاحیت میں سدھار کیلئے 162 کلومیٹر پری فیریل سیور لائن کا انتخاب ٹرنچ لیس ٹکنالوجی کے ساتھ انہیں نیا روپ دینے کیلئے کیا گیا ہے۔ اس سے پرانی سیور لائنوں کی ویلڈٹی 50 سال تک بڑھ جائے گی۔

گھر اور شہری ترقی

سرکار غیر قانونی کالونیوں میں سڑکوں اور نالوں کی تعمیر، پانی کی فراہمی، سیور نظام، صفائی اور گلیوں میں لائٹ وغیرہ بنیادی شہری سہولتیں مہیا کرنے پر زور دے رہی ہے ان کاموں کیلئے خاص طور سے عملدرآمد ایجنسیوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے۔ جن میں ڈی ایس آئی آئی ڈی سی، آئی اینڈ ایف سی اور دہلی جل بورڈ شامل ہیں۔ دہلی سرکار نے 11 دسمبر 2017 کو دہلی سلم اور جے پیئر واس اور دوبارہ بسانے نیتی کی اطلاع دی گئی ہے۔ اس کا مقصد جھگی جھونپڑی بستیوں کا اسی زمین پر بحالی کرنا اور پانچ کلومیٹر کے دائرے میں بنائے گئے فلیٹوں میں بحالی کرنا ہے 2017-18 کے دوران 1600



سرکار نے ایک نیا پروگرام "الکحل اور نشیلی اشیاء کی روک تھام" شروع کرنے کا فیصلہ کیا

ہے۔ اس کا مقصد دہلی میں نشے کی عادت چھڑانے اور بحالی خدمات فراہم کرنے کے پروگرام کو مضبوطی فراہم کرنا اور اس جانب میں مکمل پیمائش کرنا ہے۔ اس پروگرام میں کمیونٹی بنیادی تنظیموں کی مدد لی جائے گی۔

پانی کی فراہمی اور سیور

پچھلے سال کے آؤٹ کم بجٹ کے ریویو میں یہ بات سامنے آئی کہ دہلی میں 47 فیصدی پانی، نان ریوینیو واٹر ہے۔ یعنی دہلی جل بورڈ کو اپنے



قریب آدھے پانی کا یہی پتہ نہیں ہے کہ وہ لیک ہو رہا ہے یا چوری ہو رہا ہے۔ پہلی بار سرکار پوری دہلی میں بلک واٹر میٹر لگانے کا پرو جیکٹ لیکر آئی ہے تاکہ پتہ چلے پانی جا کہاں رہا ہے سبھی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سبھی پرائمری اور سکندری یو جی آر اور سبھی ٹپنگ پرمیٹر لگائے جائیں گے اس سے پانی کی چوری پکڑی جاسکے گی اور ایک طرح سے روزانہ پانی کا آؤٹ ہوگا۔ اس سے بلک واٹر میٹرس کا پورا ڈیٹا ویب سائٹ پر ڈالا جائے گا تاکہ دہلی واسیوں کو بھی پتہ رہے کہ ان کی کالونی میں دہلی جل بورڈ کی جانب سے کتنا پانی آ رہا ہے اور وہ کہاں جا رہا ہے۔

دہلی سرکار سیویج ٹریٹمنٹ کے پورے تصور کو بدلنے پر کام کر رہی ہے پہلے دہلی میں بڑے بڑے سیویج ٹریٹمنٹ لگائے گئے ہیں ان سے ٹریٹ ہو کر پوری دہلی میں لگ بھگ ساڑھے چار سو ایم جی ڈی پانی دہلی جل بورڈ کے پاس مہیا ہوتا ہے لیکن اس میں سے صرف 89 ایم جی ڈی پانی ہی ابھی استعمال ہو رہا ہے اور باقی 361 ایم جی ڈی پانی روزانہ سینا میں بہا دیا جاتا ہے۔ اس

دیگر کچھڑے لوگوں اور اقلیتوں کے بہبود کے تین عہد بند ہے اور مطابق ان کے بہبود کیلئے بہت سے پروگرام لاگو کر رہی ہے۔

سرکار قریب سات لاکھ فائدہ مندوں کو مالیاتی مدد فراہم کر رہی ہے جن میں سینئر سٹیزن، متاثرہ خواتین، بیوہ وغیرہ شامل ہیں۔ سرکار نے امتزاج بال وکاس پروگرام کے تحت 10897 آنگن واڑی مراکزوں میں خدمات کا درجہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے جو لگ بھگ 12 لاکھ بچوں اور خواتین کو غذائیت، صحت خدمات، ٹیکا کرن اور اسکول۔ قبل سرگرمیوں سے ملحقہ وغیرہ کو خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔

سرکار سبھی آنگن واڑی مراکز میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گی اور آنگن واڑی کام کرنے والوں کو موبائل فون مہیا کرائے گی جس سے آئی سی بی ایس پر وجیکٹ کے تحت خدمات اور پروگراموں کی کافی نگرانی اور پورٹنگ کرنے میں مدد ملے گی۔ سال 2018-19 کے دوران پرتساہت آنگن واڑی انین پروگرام کے تحت محکمہ بچوں کیلئے میز، کرسی، چٹائی، کھلونے وغیرہ مہیا کراتے ہوئے ماڈل آنگن واڑی مرکز بنائے گا۔ ایک نیا پروگرام "ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن" کے بارے میں ابھی سرپرستوں اور آنگن واڑی سمیٹیوں کیلئے ٹریننگ بھی شروع کی جائے گی۔

ایس ٹی اور ایس سی، اقلیت سے متعلق طلباء کیلئے لاڈلی اسکیم کے پیٹن پر 18 سال کی عمر تک کے طلباء کے نام پر فلکسڈ ڈپوٹ ٹ یوجنا شروع کی جائے گی۔ سرکار نے جے بھیم مکھیہ منتری ٹیلنٹ یوجنا نام کا ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت دہلی کے اسکول سے کلاس دسویں اور بارہویں پاس یا بارہویں میں پڑھنے والے ایس سی ایس ٹی طلباء کو یقینی طور پر نجی کو چنگ اداروں میں کو چنگ فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ مختلف مسابقتی امتحانات پاس کر سکے ایسے ایس سی طلباء کو مفت کو چنگ فراہم کی جاتی ہے جن کے خاندان کی سالانہ آمدنی دو لاکھ روپے تک ہو اور اگر خاندان کی آمدنی چھ لاکھ روپے تک ہوگی تو سرکار 75 فیصدی فیس برداشت کرے گی اس کے علاوہ ایس سی طلباء کو 2500 روپے ہرمینے اسٹائپنڈ کو چنگ کے دوران چار سے پانچ مہینے تک دیا جائے گا۔

بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں کوئی حادثے ہونے یا کوئی اور ایمرجنسی حالات میں متاثرہ لوگوں کو جلدی اسپتال پہنچانے کیلئے "پہلی امداد کی گاڑی" فرسٹ ریسپانڈر ویکل (ایف آروی) مہیا کرنے کے ایک تجربہ کار پروگرام کو منظوری دی گئی ہے۔ تربیت ایسبولینس کارمیکوں کے ذریعہ آپریننگ 16 موٹر سائیکلوں کے ساتھ یہ پروگرام مشرقی دہلی میں شروع کیا جائے گا۔ اس سے تنگ گلیوں اور بھیت بھرے علاقوں میں بچاؤ کارروائی فاسٹ آپریٹ کرنے میں مدد ملے گی۔

سبھی اسمبلی حلقوں میں مریض ویلفیئر کمیٹی بنائی جائیں گی۔ اور ہر ایک عوامی صحت مراکز جیسے محلہ کلینک، پولی کلینک اور دہلی سرکار کی ڈسپینسریوں و سیڈ پی یو ایچ سی میں اسکی ذیلی کمیٹی کے طور پر ایک عوامی صحت سمیٹی قائم کی جائیں گی۔ اس کا مقصد صحت دیکھ بھال خدمات کے منجمنٹ میں بہتر کمیونٹی بھاگیداری یقینی بنانا ہے۔ صحت دیکھ بھال خدمات فراہم کرنے والے موبائل وین کلینکوں کو قائم کیا جائے گا جو خاص طور سے آنکھ اور کان سے متعلق خدمات فراہم کریں گے۔ سال 2018-19 میں اس پروگرام کیلئے 15 کروڑ روپے تجویز کردہ ہیں۔

نائب وزیر اعلیٰ منیش سوسو دیا نے کہا ہے کہ سرکار دہلی کے شہریوں کو لسیڈ پرائیویٹ اسپتالوں اور سرکاری اسپتالوں میں علاج کی سہولتیں فراہم کرنے کیلئے سب کیلئے صحت بیمہ پروگرام شروع کرے گی اس پروگرام کے توسیع جہت رہنمائی تیار کرنے کیلئے سمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے۔

سماجک حفاظت اور بہبود

سرکار سماج کے غریب اور نظر انداز کلاسوں، خاص طور سے متاثرہ خواتین، سینئر سٹیزن، معذور لوگوں، ایس سی ایس ٹی، اور





پروگرام شروع کیا تھا اب اس پروگرام کو توسیع کرتے ہوئے اس کے دائرے میں دیگر صوبوں دہلی سے باہر، لیکن ہندوستان میں موجود کیندر سنسٹھان میں ایجوکیشن حاصل کرنے والے طلباء کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

دہلی، بیشک، خوشحال امانت، اور ثقافتی کا خزانہ ہے۔ دہلی کی امانت کے متعلقہ میں دنیا بھر کے ریسرچس کو آگاہ کرانے اور انہیں آگے کے ریسرچ کیلئے حوصلہ افزائی کرنے کیلئے سرکار نے آرکائیول ریکارڈس کے ڈیجیٹائزیشن کرنے اور ان کی مائیکروفلم بنانے کی ایک مہذب اسکیم شروع کی ہے۔ یہ پروجیکٹ سات مہینے پہلے شروع کیا گیا تھا اور اب تک 20 لاکھ آرکائیول ریکارڈس کا ڈیجیٹائزیشن کیا جا چکا ہے۔ اپریل 2018 تک یہ خدمات ملک اور دنیا کے ریسرچس کیلئے مہیا ہو جائے گی۔

دہلی میں آرٹ اور ثقافتی کا حوصلہ افزائی کرنے اور حفاظت و تحفظ کیلئے 2018-19 میں کچھ نئے پروگرام لاگو کرنے کی تجویز ہے نئے پروگراموں کے عمل کیلئے اس سال بجٹ میں 36 کروڑ روپے تعین کئے گئے ہیں ان پروگراموں میں 13 نئی زبانیں اکادمیوں کی قیام ایک انگریزی زبان کی اکادمی اور اسٹیٹ لیول ڈانسنگ و گائین ٹیلیٹ کھوج کیلئے سالانہ سیریزوں کی تیاری بھی اسمبلی حلقوں کے علاقوں میں ثقافتی سرگرمیوں کی تیاری اور آثارِ قدیمہ و ریکارڈ میں ریسرچ فیلوشپ وغیرہ شامل ہیں۔

صحت

دہلی میں تین درجے کے صحت مند فریم تیار کئے جا رہے ہیں۔ جس میں محلہ کلینک، پولی کلینک اور اسپتال شامل ہیں دہلی کے باشندوں کو ان کے گھر کے پاس صحت دیکھ بھال خدمات مہیا کرانے کیلئے ابھی تک 164 عام آدمی محلہ کلینک انسٹال کئے جا چکے ہیں اب تک قریب 80 لاکھ لوگوں نے محلہ کلینکوں میں علاج خدمات کا فائدہ اٹھایا، محلہ کلینکوں کی قیام کیلئے 530 جگہوں کا انتخاب کیا گیا ہے اور سرکار کا مقصد ایک ہزار محلہ کلینکوں کی تعمیر کرنے کا ہے اسی طرح 24 پولی کلینک کام کر رہے ہیں اور 94 ڈسپنسریوں کی

پہچان کی گئی ہے جہاں ایسے پولی کلینک شروع کئے جائیں گے۔ اس سے سرکاری اسپتالوں پر بوجھ کم کیا جاسکے گا۔

سرکار دہلی کے شہریوں کو بہتر صحت دیکھ بھال خدمات فراہم کرنے کیلئے اسپتالوں میں بستروں کی کل تعداد موجودہ دس ہزار سے بڑھا کر بیس ہزار پہنچانے کیلئے عہد پابند ہے۔ امبیڈ کرنگر میں 600 بستروں کا اسپتال اور براڈی میں 800 بستروں کا اسپتال سال 2018-19 میں تیار ہو جائے گا۔ دوارکا میں 1500 بستروں کے اسپتال کی تعمیر کا کام پیشگی مرحلے میں ہے۔ دہلی سرکار کے سات موجودہ اسپتالوں میں 2546 نئے بستر جوڑے جائیں گے۔ مادی پور، جوالا ہیڑی، ہسٹنسال، سرینا ہار، دیندار پور، کیشو پورم اور چھتر پور میں نئے اسپتالوں کی تعمیر کی اسکیم تیار کی جا رہی ہے۔

دہلی کے سبھی سرکاری اسپتالوں میں آنے والے مریضوں کے ڈائیکٹو سٹک ٹیسٹ مفت کئے جاتے ہیں اتنا ہی نہیں دہلی سرکار کے صحت مراکز کے ذریعے ریفر کئے جانے پر مخصوص لسٹیڈ پرائیویٹ مراکز میں ایم آر آئی، سی ٹی، پی ای سی ٹی، ریڈیو نیوکلیئر اسکین، الٹرا ساؤنڈ، کلرڈوپلر، ایکو، ٹی ایم ٹی، ای ای جی اور ای ایم جی جیسی ریڈیو لو جیکل خدمات بھی سبھی مریضوں کیلئے مفت ہیں۔

سرکار نے دہلی میں ہوئے سڑک حادثوں کے سبھی متاثرین، ایسڈ حملوں کے متاثرین اور تھرمل یا سوزش سے جملے زخمیوں کے خرچ کی لاگت برداشت کرنے کا بھی فیصلہ لیا ہے۔ بھلے ہی ایسے متاثرین آدمیوں کی آمدنی کتنی ہی کیوں نہ ہو اور وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو اس کے علاوہ دہلی سرکار کے 24 اسپتالوں کے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مریضوں کو 48 لسٹیڈ پرائیویٹ اسپتالوں میں مفت سرجری کیلئے بھیج سکتے ہیں۔

DELHI BUDGET 2018

وزیر خزانہ نے اپنے بجٹ خطاب میں فخر کے ساتھ کہا تھا کہ یہ ورلڈ کلاس کوشل وکاس مرکز جو کہ آئی ٹی ای سنگاپور کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے

نے سو فیصدی پلیسمنٹ یعنی نوکری دلانے کا ریکارڈ مسلسل بنائے رکھا ہے۔ اور کوشل وکاس پروگرام کا ماڈل کامیابی سے لاگو کیا گیا ہے۔ سرکار نے کوشل ماڈل کا تقلید کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جس کے تحت دہلی میں 25 نئے ورلڈ کلاس کوشل وکاس مراکز کھولے جائیں گے۔ اس کا مقصد ہر سال قریب 25 ہزار جوانوں کو تربیت فراہم کرنا ہے انہوں نے بتایا کہ 2018-19 کے دوران 25 نئے ورلڈ کلاس کوشل وکاس مراکز کھولنے کی تجویز ہے۔

اعلیٰ تعلیم کو انوڈیبل بنانے کیلئے دہلی سرکار نے سات یونیورسٹیوں اور ان سے ملحقہ کالجوں اداروں کے مختلف بچکر کورسز و داخلہ لینے والے

طلباؤں کو مالیاتی مدد فراہم کرنے کیلئے "صلاحیت و اقتصادی حالات سے متعلق مالیاتی مدد" نام سے پروگرام شروع کیا ہے اس پروگرام کے اندر نیشنل فوڈ سیکورٹی کوڈ رکھنے والے اسٹوڈینٹوں کو سو فیصدی ٹیوشن فیس کے برابر مالیاتی تعاون دی جاتی ہے جو طلباء کسی فوڈ سیکورٹی پروگرام کے تحت کور



نہ کئے گئے ہوں اور جن کے خاندان کی سالانہ آمدنی 2.50 لاکھ روپے سے کم ہو وہ بھی ٹیوشن فیس کی ادھی رقم (50 فیصدی) کے برابر رقم مالیاتی تعاون کے طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ 2.50 لاکھ روپے سے زیادہ لیکن 6 لاکھ روپے تک سالانہ خاندان آمدنی والے طلباء اس پروگرام کے تحت ٹیوشن فیس کے 25 فیصدی کے برابر مالیاتی تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔

دہلی میں دسویں / بارہویں کلاس پاس کرنے کے بعد اعلیٰ درجے کی تعلیم میں جانے والے طلباء کو لون مدد دینے کے لئے 2016-17 میں سرکار نے دہلی اعلیٰ تعلیم اور کوشل وکاس لون گارنٹی

تیار کرنے کے واسطے مالیاتی مدد دی جائے گی۔ ان دونوں پروگراموں کیلئے 2018-19 کے بجٹ میں 35 کروڑ روپے کے بجٹ کا منصوبہ کیا گیا ہے۔

مقامی سطح پر محلہ اور کالونیوں میں کھیلوں میں عوام کو امنگ و جوش بھرنے و حصہ لینے کیلئے مختلف اسمبلی حلقوں میں کھیل کود کا انعقاد کیا جائے گا۔ ان پروگراموں کیلئے 2018-19 میں 20 کروڑ روپے کا بجٹ تجویز کردہ ہے۔

اعلیٰ تعلیم کے حلقہ میں اندر پرستھ ٹکنالوجی سنسٹھان، آئی آئی آئی ٹی، کے کیمپس کی تعمیر کا دوسرا مرحلہ 250 کروڑ روپے کی لاگت سے پورے زور شور سے جاری ہے اور جلد ہی اسے پورا کر لیا جائے گا۔

آئی آئی آئی ٹی میں داخلے کیلئے سیٹوں کی تعداد 1200 سے بڑھا کر 2500 کی جا سکے گی۔ شہید سکھ بوجا کالج آف بزنس اسٹڈیز کا تعمیراتی کام 132.47 کروڑ روپے کی لاگت سے پورا کر لیا گیا ہے۔ دہلی ٹکنالوجی یونیورسٹی - ڈی ٹی یو کا مشرقی کیمپس

چالو ہو گیا ہے، جس میں 300 سیٹیں ہیں، جنہیں ملا کر ڈی ٹی یو میں سیٹوں کی تعداد جو 2014-15 میں 2564 تھی، وہ 2017-18 میں بڑھ کر 3689 ہو گئی ہے۔

روہنی اور دھیر پور میں امبیڈکر یونیورسٹی کے نئے کیمپس کی تعمیراتی کام

2018-19 میں شروع کرنے کا منصوبہ ہے۔ گرو گو بند اندر پرستھ یونیورسٹی کے مشرقی کیمپس کی تعمیر اگست 2017 میں 271 کروڑ روپے کی لاگت سے سورجمل و ہار میں شروع کیا گیا ہے۔

جی جی ایس آئی پی یو میں سیٹوں کی کل تعداد 2017-18 میں بڑھ کر 34094 ہو گئی۔ دہلی ٹکنالوجی یونیورسٹی کے نئے مشرقی پریسر نے تعلیمی سال 2017-18 سے کام کرنا شروع کر دیا، دوسرے مرحلہ کے دوران دہلی ٹکنالوجی یونیورسٹی اور این ایس آئی ٹی کے موجودہ پریسروں کا توسیع کرنے اور سیٹوں کی تعداد بڑھانے کا منصوبہ ہے۔

مشین وغیرہ لگانے کا کام چل رہا ہے۔

سرکاری اسکولوں میں لڑکیوں کیلئے سیلف ڈیفنس کلاسز شروع ہوں گی تاکہ ان کے اندر مخالف حالتوں میں خود کو محفوظ بنائے رکھنے کا خود اعتمادی ہو اور وہ کسی بھی غیر ضروری حالات سے نپٹنے کیلئے جسمانی اور دماغی طور سے قابل ہوں۔ اس کیلئے ایجوکیشن محکمہ کے بجٹ میں دس کروڑ روپے کا الگ سے انتظام کیا گیا ہے۔

اس سال سے دہلی سرکار ایک نئی مہم لارہی ہے جس کے تحت دہلی کے ہر اسکول کا تشخیص کرائی جائے گی ان کے بچ پڑھائی کا انتظام اور معمول کو لے کر صحت مقابلہ ہوگا۔ اور لوگوں کے پاس اسکول سے متعلق سرکاری اطلاعات ہوں گے تاکہ اسکولوں کو صحیح جانب میں آگے بڑھانے کا روڈ میپ تیار کیا جاسکے اس مقصد کیلئے سرکار نے ایجوکیشن محکمہ کے ذریعہ سے 15 کروڑ روپے ڈی سی پی سی آر کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔

ڈیفنس سروسز میں نوجوانوں کی دلچسپی جگانے کیلئے دہلی سرکار نے راشن ریڈکشن اکادمی کیدٹوں کو تربیت کی مدت میں تین سال کیلئے ہر مہینے دو ہزار روپے کی مالیاتی تعاون ٹریننگ بھتہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔

وزیر خزانہ نے بتایا کہ راشن ریڈکشن اسکول کھیلوں میں دہلی اس بار بھی سب سے اوپر رہی اور اس نے ان کھیلوں میں کل ملا کر 426 گولڈ میڈل 205 سلور تمغہ، اور 169 کانسی کا تمغہ جیتے۔ سرکار نمونہ پزیر کھلاڑیوں کیلئے ورلڈ کلاس کھیل ڈھانچے کی تعمیر کرنے کیلئے عہد پابند ہے۔ کھیلوں میں اعلیٰ کامیابیاں حاصل کرنے میں کھلاڑیوں کی مدد کیلئے

سال 2018-19 میں سرکار دو پروگرام شروع کرنے جارہی ہے یہ ہیں، "کھلیو اور ترقی کرو" اور "مشن ایکسی لینس" یعنی اعلیٰ مہم، کھلو اور ترقی کرو پروگرام کے اندر 14 سے 17 سال کی عمر گروپ کے ایسے کھلاڑیوں کو مالیاتی مدد دی جائے گی جو قومی رینٹنگ الگ الگ کھیلوں میں رینٹنگ کی نظر سے سب سے اوپر ہوں اور انہوں نے دہلی کی نمائندگی کی ہو اس کا مقصد کھلاڑیوں کو کھیلوں میں اعلیٰ شراکت کرنے کیلئے حوصلہ افزائی کرنا اور انہیں نیشنل انٹرنیشنل کمپیشن میں مقابلوں کیلئے تیار کرنا ہے۔ مشن ایکسی لینس پروگرام کے اندر کسی بھی عمر گروپ کے کھلاڑیوں کو کھیلوں میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنے اور نیشنل انٹرنیشنل کمپیشن میں مقابلہ کرنے کیلئے

مشن بنیاد کے نام سے پروگرام شروع کیا جا رہا ہے اس کے تحت

دہلی سرکار اور نگرنگم کے کلاس ایک

سے آٹھ تک کے بچوں کی ریڈنگ اور میٹھ اسکس ٹھیک کرنے پر اپریل مئی اور جون کے مہینوں میں خاص مہم چلائی جائے گی۔

طلباؤں کی تحفظ اور سلامتی کو بڑھا دینے اور اسکول روشوں پر کافی نگرانی رکھنے کیلئے سبھی سرکاری اسکول عمارتوں میں قریب 1.2 لاکھ سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے جس کیلئے 2018-19 کے بجٹ تخمینہ میں 175 کروڑ روپے کی لاگت منظور کی گئی ہے۔ ہر ایک عمارت میں 150 سے 200 تک کے کیمرے لگائے جائیں گے اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ سرپرست کو اپنے بچوں کی کلاس روم کی طرز عمل سیدھے انٹرنیٹ پر دیکھنے کی سہولت بھی عطا کی جائے گی۔

ٹیچروں کو ورلڈ کلاس ٹریننگ کے ساتھ ساتھ سرکار انہیں جدید سہولتیں دینے پر بھی زور دے رہی ہے ابھی تک ٹیچروں کا بہت سا رافٹ ہر مہینے بچوں کی لسٹ بنانے اور زلٹ تیار کرنے اور اسے اپلوڈ کرنے وغیرہ میں بیکار ہو جاتا ہے سرکار سبھی اسکول ٹیچروں کو کمپیوٹر ٹیلیٹ دے گی تاکہ سبھی ٹیچر اپنے اسکول کے بچوں کا آن لائن ریکارڈ رکھ سکیں۔ ان کی حاضری، رزلٹ، اسکا لرشپ دیگر کاڈاٹا تیار کر سکیں اور ڈپارٹمنٹ بھیجنے کیلئے الگ الگ لسٹ نہ تیار کرنی پڑے اس ٹیب کا استعمال ٹیچرس کی آن لائن ٹریننگ اور ایجوکیشن کی قابلیت سدھارنے میں بھی ہوگا۔



DELHI BUDGET 2018

بردھیان مرکوز کرنے کی صلاحیت
تخلیق کرنے والے تعمیراتی
اور ضروری سوچ کو بڑھاوا دینے

والے ہوں ایجوکیشن میں ایسا مجموعی طور پر نقطہ نظر اپنانے سے
بچوں کے صحت مند دماغ کے تعمیر اور انہیں خوشحال زندگی جینے میں موزوں
بنانے میں مدد ملے گی۔

انہوں نے کہا کہ دہلی کے سرکاری اسکولوں میں جو بدلاؤ آیا ہے اس میں
اسکول مینجمنٹ کمیٹی یعنی ایس ایم سی کا بڑا تعاون رہا ہے۔ ایس ایم سی کے
16 ممبروں میں سے 12 سرپرست ہوتے ہیں اس کمیٹی بھاگیداری سے
اسکولوں میں جواب دہی بڑھی ہے اس لئے اس سال سے ہر اسکول کی ایس
ایم سی کو پانچ لاکھ روپے کا فنڈ دیا جائے گا جس سے وہ اسکولوں میں
لابریری کیلئے کتابیں خریدنے، پڑھائی پروجیکٹ بنانے کیلئے ٹیچروں کی
سہولت کیلئے ٹیچنگ ایڈس خریدنے و چھوٹی چھوٹی مرمت کا کام کرا سکے گی
ساتھ ہی ایس ایم سی شوٹ ٹرم پیس پر رسوں پر سن رکھ پائے گی جو
طلباؤں کو میوزک، آرٹ، ڈانس، آئی ٹی میڈیکل کی تیاری یا مزید
کلاسز کرا سکے گی اس فنڈ کے استعمال کے فیصلے ایس ایم سی کی مٹینگ میں
ہی ہوں گے۔ اس کے لئے اسکول کسی پر انحصار نہیں ہوگا۔

پچھلے دو سالوں میں میگھانی ٹی ایم کے ذریعہ سے سرپرستوں کو
اسکولوں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے کیوں کہ سرکار مانتی ہے کہ
ایجوکیشن کامیاب ہونے کیلئے اسکول اور گھر کے جامع کوششوں کی
ضرورت ہے۔ اسی پہل کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم سرکاری اسکولوں
میں پینٹس ورکشاپ بھی شروع کریں گے تاکہ ماں باپ اپنے بچوں کی
پڑھائی میں فعال و مثبت کردار نبھاسکے۔

ایجوکیشن حق قانون کے حوالہ میں اسٹوڈنٹس ٹیچر تناسب بنائے
رکھنے کیلئے تعلیمی ڈھانچے میں مسلسل بہتر تری کی کوشش کی گئی ہے
12748 اضافی کلاس روم کی تعمیر 30 نئے اسکول بلڈنگ اور 366
سرودید و دیالیہ میں نرسری کلاسیں شروع کرانے کی مہم بنائی گئی ہے۔ 155
سرودید و دیالیہ میں پری پرائمری کلاسیں پہلے ہی شروع کی جا چکی
ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سرکار نے 144 اسکولوں میں کامرس کی پڑھائی
بھی شروع کی ہے۔

ایلیمنٹری کلاسوں کے بچوں کے ذریعے اپنی ٹیکسٹ بک پڑھانے اور
بیسک میٹھ اسکول ڈیولپ کرنے کے مقصد سے سرکار نے 'چونو 2018'
پروگرام شروع کیا تھا اس کے اچھے نتیجوں کو دیکھتے ہوئے اب اسی طرز پر



اضافی کلاس روم، نئے اسکول بھون، کھیل کے میدان، سوچہ بیت الخلاء
سہولتوں دیگر کی تعمیر کے حوالہ میں بنیادی ڈھانچہ سہولتوں کے فروغ کے لئے
بھاری سرمایہ کاری کو ترجیح دی گئی ہے۔ تعلیم کی معیار میں سدھار، موجودہ
کالجوں میں پری اسکول کلاسز شروع کرنا، تعلیم کو دلچسپ بنانا، اور تعلیم کو کھیل
روشوں کے ساتھ جوڑنا، دیگر ایسے امکان والے حلقہ ہیں، جن پر دہلی سرکار
2018-19 کے دوران زور دے گی۔ سرکار نے چابکدستی ترقی پروگرام میں
سدھار لانے، اعلیٰ درجے کی تعلیم میں زیادہ تعلیمی موقع مہیا کرنے،
کالجوں کو اشکال رشپ کے ذریعے اعلیٰ درجے کی تعلیم کو حوصلہ افزائی کرنے
اور تحقیق و ترقی کی روشوں کو بڑھاوا دینے پر بھی دھیان مرکوز کیا ہے۔

جناب سسودیانے کہا کہ سرکار نے پہلے سال میں اسکولوں کے بنیادی
ڈھانچے کو درست کرنے کا کام تیزی سے کیا۔ اب یہ کام اپنی رفتار پکڑ چکی
ہے۔ اس کے بعد دوسرے سال سے اساتذہ کا اخلاقی قوت بڑھانے
اور انہیں ورلڈ کلاس ٹریننگ دلانے کا کام شروع کیا۔ یہ کام بھی اب اچھی
رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگلے سال سے ہماری سرکار دہلی کے سرکاری
اسکولوں میں ایک نیا کورس - پی ٹی نیس کری گلم کے نام سے لیکر آرہی
ہے۔ اس کے تحت نرسری سے درجہ 8 تک کے بچوں کیلئے الگ طرز عمل،
تیار کی جا رہی ہے، تاکہ کم عمر میں ہی بچوں کو خوش رہنے، خود اعتمادی،
کمائی کرنے اور اپنی شخصیت کی ترقی کرنے کی ٹریننگ دی جاسکے۔
اس کیلئے کورس میں ایسے جزئے ترکیبی شامل کی جائیں گی جو خود اعتماد
اور ذمہ داری کی احساس پیدا کرنے والے اور تناؤ و فکر کرنے والے
ہوں اور ساتھ ہی اداسی سے بچنے میں مددگار اور ایجوکیشن و کام

ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ لیتے وقت کم سے کم انسانی مداخلت اور اس کی باریکیوں کو تکنیکی مدد سے جانچنا۔ سرکار اگلے کچھ ہفتوں میں روڈ سیفٹی پالیسی کا ڈرافٹ جاری کرے گی اور جلد ہی سڑک تحفظ کیلئے روڈ سیفٹی فنڈ بھی انسٹال کیا جائے گا۔ 2018-19 کے دوران ڈی ٹی سی کے بڑے اسٹنڈرڈ سائز کی 1000 بسوں کو جوڑنے کا کام شروع ہو جائے گا۔ بسوں میں الیکٹرونک ٹکٹنگ کے ذریعہ خود بخود کرایہ اکٹھا کرنے کا انتظام کلکسٹر بسوں میں پوری طرح لاگو کر دی گئی ہے۔ ڈی ٹی سی نے بھی اپنی بسوں میں الیکٹرونک ٹکٹنگ مشینیں نظام لاگو کرنا شروع کیا ہے۔ ایک موبیلیٹی کارڈ کی سہولت کی ایک تجرباتی منصوبہ کی شروعات جنوری 2018 سے ڈی ٹی سی کی 200 اور 50 کلکسٹر بسوں میں شروع کی گئی ہے۔ اسے اپریل 2018 سے سبھی بسوں میں لاگو کئے جانے کا منصوبہ ہے۔ ان میں اے ٹی ایم کا استعمال کرتے ہوئے کرایہ کا بھگتان دہلی میٹروپولیٹن کارڈ کے ذریعہ کیا جاسکے گا۔

ڈی ٹی سی کے ذریعہ خریدی جانے والی نئی بسوں اور کلکسٹر منصوبہ کے تحت شامل کی جانے والی بسوں کی پارکنگ کیلئے سات بس ڈپو۔ ڈھچاؤں کلاں 2، بوانہ سیکٹر 1، ریلوہ خانپور، رانی کھیڑا 1، رانی کھیڑا 2، رانی کھیڑا 3 اور دوار کا سیکٹر 22 میں پورے کر لئے گئے ہیں۔ کھرہری نہر کا بس ڈپو مارچ 2018 میں پورا کر لیا جائے گا۔ سال 2018-19 میں چھ نئے بس ڈپو گھومس ہیڈ، منڈیلا کلاں، رونی سیکٹر 37، ایسٹ وڈنگر، بوانا سیکٹر 5 اور وی آئی یو براڈی میں بھی بنائے جائیں گے۔

سرکار نے محفوظ عوامی نقل و حمل کے لئے کئی قدم اٹھائے ہیں۔ ڈی ٹی سی کی راتری سیوا میں توسیع پر 24 روٹوں پر 85 بسیں چلائی جا رہی ہیں جبکہ پہلے آٹھ روٹوں پر 38 بسیں ہی چلتی تھیں۔ ڈی ٹی سی مہیلا یاتریوں کی حفاظت کیلئے بس ڈرائیوروں کو مہیلاؤں کے برعکس حساس بنانے کا ایک پروگرام مسلسل چلا رہا ہے۔ خواتین مسافر کی حفاظت کیلئے ڈی ٹی سی کی بسوں میں 2370 سول ڈیفنس مارشل اور 120 ہوم گارڈ تعینات کئے گئے ہیں۔

ایجو کیشن

سرکار دہلی کو ایک تعلیمی مرکز بنانے کی جانب میں دور اندیشی اور ایمانداری سے کام کر رہی ہے 2018-19 کے بجٹ منقسم میں تعلیمی حلقہ کی حصہ داری سب سے زیادہ 26 فیصدی ہے۔ تعلیمی حلقے میں

اس کی شروعات بجلی محکمہ اپنے تحت عمارتوں سے کرے گی۔ سرکار اگلے سال سے دہلی میں بننے والی نئی کمرشل بلڈنگ پر بجلی کھپت کم کرنے کیلئے انرجی کنزرویشن بلڈنگ کوڈ (ای سی بی سی) لاگو کرے گی یہ کوڈ سوکرواٹ یا اس سے زیادہ کی کھپت والی عمارتوں یا 500 اسکوائر میٹر سے بڑے پلاٹ پر بنی عمارتوں پر لاگو ہوگا۔

نقل و حمل

دہلی میں رجسٹرڈ نجی گاڑیوں کی کل تعداد دوسرے مہانگروں میں رجسٹرڈ نجی گاڑیوں کی تعدادوں سے بہت زیادہ ہیں۔ اس سے نہ صرف سڑکوں پر بھاری گاڑیوں کی بھیڑ رہتی ہے بلکہ سڑک حادثے بھی ہوتے ہیں۔ اور ایندھن بیکار ہوتا ہے اس خطرناک حالت سے نمٹنے کیلئے سرکار دہلی میں پبلک نقل و حمل کے نظام میں سدھار کیلئے مسلسل کوشش کر رہی ہے۔

ڈی ٹی سی ملازمین اور پنشن والوں کو ان کے مطابق اور دوسرے بھتے وقت پر ساتویں پے کمیشن کے مطابق دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ 41000 ملازمین اور پنشن والوں کو ملے گا۔

2017-18 کے دوران سرکار نے ناممکن کوشش کر کے دس ہزار نئے آٹو پر مٹ کو منظوری دی اس میں سے 8600 پر مٹ جاری کئے جا چکے ہیں اور باقی جلد جاری کر دیئے جائیں گے۔

دہلی میں سڑکوں کو محفوظ بنانے کیلئے سرکار نے بارہ آٹو موڈ ڈرائیونگ ٹیسٹ ٹریک پر کام شروع کیا ہے ماروتی سوزو کی فاؤنڈیشن کی تعاون سے یہ منصوبہ 2018-19 میں پورا ہو جائے گا۔ اس کا مقصد



DELHI BUDGET 2018

عناصر کا اخراج نیچے لانے میں
کامیابی ملتی ہے۔

سرکار سٹی و صبا بنیادی بجلی پیداوار
مراکز سے آئیوا لے سالوں

میں 1000 میگا واٹ گرین پاور خریدے گی دہلی میں سٹی توانائی کے
استعمال کو بڑھاوا دینے کیلئے سرکار نے طے وقت کیلئے ایک حوصلہ افزائی اسکیم
شروع کی ہے اس کے تحت گھریلو بجلی صارفین کے ذریعہ لگائے گئے سٹی توانائی
نی نیٹ میٹر کنکشن سے پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر تین سال کیلئے دو روپے فی یو
نٹ کے در سے سٹی توانائی خریدنے کی حوصلہ افزائی دی جا رہی ہے۔

سرکار اسکولوں، منڈیوں اور مختلف سرکاری عمارتوں پر سولر پینل لگوانے
کیلئے ایک گروپ نیٹ میٹرنگ پالیسی لائے گی تاکہ دہلی میں وافر مقدار
میں موجود سولر سٹم کا صحیح استعمال کیا جاسکے۔

اس سال کے گرین بجٹ میں سرکار پائلٹ درجے پر ایگری کلچر۔ کم
سولر فارم اسکیم کے نام سے ایک نیا منصوبہ لا رہی ہے اس کے تحت دہلی
کے کھیتوں میں فصل کی اونچائی سے اوپر اٹھا کر سولر پینل قائم کرنے کو
حوصلہ افزائی دینے کا منصوبہ ہے اس پر دنیا بھر میں استعمال ہو رہے ہیں
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں کسان سولر پینل پیداوار کے ساتھ ساتھ
اپنی کھیتی بھی جاری رکھ پاتے ہیں اس سے دہلی میں کھیتی باڑی میں لگے
لوگوں کو اضافی آمدنی ہوگی۔

سرکار بلڈنگ انرجی ایفی شینشی پروگرام اگلے سال سے لاگو کرنے جا رہی
ہے اس کے تحت مختلف دفاتر و عمارتوں کا پاور کنجمنشن اوڈٹ کیا جائے گا



لگا کر اسے تیار کیا جائے گا۔

پی ڈبلو ڈی کی سڑکوں پر لگی لائٹس کو ایل ای ڈی لائٹس میں
بدلنے کا کام ایسکو ماڈل کے تحت کیا جائے گا۔ پی ڈبلو ڈی کی
سڑکوں پر ایک پائلٹ اسکیم کے تحت 16 کلومیٹر لمبے سائیکل ٹریک
پر سولر سٹم لگائے جائیں گے۔

توانائی

تین سال پہلے سرکار نے آتے ہی دہلی کے عام گھریلو صارفین کیلئے
آدھی قیمت میں بجلی دستیاب کرانا شروع کر دیا تھا اور تب سے یعنی
پچھلے تین سال میں دہلی میں بجلی کے دام نہیں بڑھے ہیں یہ اپنے
آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ سستی بجلی سے دہلی کے عام آدمی کے
خاندان کی اقتصادی حالت تو مضبوط ہوتی ہی ہے دہلی کی اوور آل
ایکونومی پر بھی اس کا مثبت اثر پڑا ہے۔ آج دہلی میں قریب
37.28 لاکھ گھریلو بجلی صارفینوں کو تین سال پہلے کے مقابلے
آدھی قیمت پر بجلی مل رہی ہے جو کہ دہلی میں گھریلو صارفینوں کا
82.84 فیصدی ہے یہ منصوبہ آگے بھی جاری رہے گا اور اس کے
لئے بجٹ میں 1720 کروڑ روپے کی تجویز ہے۔

شعبہ توانائی کے تحت آنے والے رینوول انرجی کیلئے کئی ایسی پہل
کی جا رہی ہے جس سے فاسل۔ فیول بنیادی بجلی پیداوار پر دہلی کی
انحصار کم سے کم ہو سکے۔ دہلی میں کل رینو ایبل انرجی صلاحیت
فروری 2018 تک 133.13 میگا واٹ تھی، جس
میں 81.13 میگا واٹ سٹی توانائی اور 52 میگا واٹ کچرے
سٹیوانائی پلانٹس سے ملنے والی بجلی شامل ہے۔ 74 میگا واٹ سٹی توانائی
فروغ کا کام ترقی پر ہے۔ اس سے دہلی میں کاربن دوسرے آلودگی



فائدہ ان سبھی ای-رکشمالکوں کو بھی دیا جائے جو ایک جولائی 2015 سے یکم اپریل 2016 کے بیچ رجسٹرڈ کئے گئے ہیں اس طرح یکم جولائی 2015 سے یکم اپریل 2016 کے بیچ رجسٹرڈ سبھی ای-رکشمالکوں کو 30,000 روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ بھلے ہی ان کی درخواست محکمہ میں زیر غور ہوں یا انہوں نے نئے سرے سے درخواست کیا ہو۔ اس کے علاوہ ایئر-ٹینینس-فنڈ سے 15,000 روپے ان ای-رکشمالکوں کو بھی دیئے جائیں گے جنہوں نے 15,000 روپے کی پرانی در سے ادائیگی کی گئی تھی۔

دہلی میں الیکٹرک موپیلیٹی کو اور بڑھا دینے کے لئے سرکار مفصل الیکٹرک وہیکل پالیسی تیار کر رہی ہے۔ اس میں خاص کر کے بی ایس-2 اور بی ایس-3 دو پہیہ گاڑیوں اور ٹیکسی، کمرشل گڈس کیریئرز کو الیکٹرک وہیکل میں بدلنے کا خاکہ بنایا جائے گا۔ نجی استعمال کیلئے خریدی جانے والی الیکٹرک کاروں پر تو سرکار پہلے ہی سبسڈی دے رہی ہے اس کے ساتھ ہی نجی کاروں کے خریداروں کیلئے پیٹرول یا ڈیزل کی جگہ سی این جی فیکٹری فیڈ کا خریدنے پر سرکار پچاس فیصدی رجسٹریشن چارجز میں چھوٹ کا بندوبست کرے گی۔

دہلی میں اوور لوڈیڈ ٹرکس کیخلاف مہم چلانے کیلئے نقل و حمل محکمہ کے انفورسمنٹ ونگ کو مضبوط کیا جا رہا ہے اس کے لئے براڑی، سرائے کالے خان اور دوارکا میں موجود امپاؤنڈنگ پٹس پروینگ برج بنائے جائیں گے۔ نگرانی کیلئے 60 نئے گاڑیوں، باڈی کیمرہ اور ای چالاننگ ٹیب خریدے جائیں گے۔

گاڑی آلودگی پر کنٹرول کے لئے پولیوشن انڈر کنٹرول (پی یو سی) پروگرام کو اور با اثر بنایا جا رہا ہے۔ اس کے تحت گاڑی کے مالکوں کو ایس ایم ایس اور فون سے ریمائنڈر بھیجنا اور پی یو سی سینٹرس کا تھڑ پارٹی اوڈٹ کرانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اس بندوبست کو کامیاب بنانے کیلئے دنیا کے مشہور ٹکنالوجی سنسٹھان ایم آئی ٹی اور یونیورسٹی آف شکاگو کے ریسرچ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔

پی ڈبلو ڈی محکمہ

دہلی میں سڑک کنارے اور گاڑیوں سے اڑنے والی دھول آلودگی کی ایک بڑی وجہ ہے اس فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے سرکار پی ڈبلو ڈی کی سڑکوں کی لینڈ اسکپنگ کی مہم لا رہی ہے۔ اس کے تحت سڑک پر دھول نہ اڑے اس کیلئے سڑکوں کے آس پاس کی سبھی کچی جگہوں کو گھاس اور پودے

اور اس کیلئے 30 ہزار روپے تک کی امدادی رقم سرکار کی جانب سے دی جائے گی۔

دہلی کے باشندوں کو آلودگی کے خلاف لڑائی میں شرکاء بنانے اور اس کے خطرے کے برعکس ہر پل ہوشیار رہنے کے مقصد سے پبلک ڈیننگ والے سرکاری دفاتروں میں فضائی آلودگی کے لیول کی جانکاری دینے والے قریب ایک ہزار انڈور ڈسپلے پینل لگائے جائیں گے۔ دہلی میں فضائی آلودگی کے حالات کے پیش گوئی کیلئے ورلڈ بینک کی ٹیم کے مشیر سے ایک ماڈل ڈیولپ کیا جائے گا تاکہ کسی خاص صورت حال کی وجہ سے، جیسے کی سردی کے دوران دہلی میں اسموگ کی مقدار اچانک بڑھتی ہے، انکی جانکاری پہلے سے ہو سکے۔

محکمہ نقل و حمل

وزیر خزانہ نے کہا کہ سرکار دہلی کے ڈی ٹی سی اور کلکسٹر بس سمیت پورے بس بیڑے کو ماحول کے مطابق فیول ٹکنالوجی کی جانب لے جانے کے برعکس عہد بند ہے۔ آئندہ سال میں دہلی میں 1000 الیکٹرک بسیں لانے کی تیاری ہے۔ یہ ملک کے کسی بھی شہر میں الیکٹرک بسوں کا سب سے بڑا بیڑا ہوگا۔ درحقیقت چین کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی ملک میں سب سے بڑا۔

اس کے ساتھ ساتھ محکمہ نقل و حمل میٹرو اسٹیشن کے پاس لاسٹ-مائل -کٹیکٹ ویٹی دینے کیلئے ڈی ایم آر سی کے بیڑے میں بھی 905 الیکٹرک فیڈر گاڑی شامل کرانے میں مدد کر رہا ہے۔ 2016-17 کے بجٹ میں ای-رکشمالکوں کو 30,000 روپے کی یک مشنت سبسڈی دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اب سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ



DELHI BUDGET 2018

شہریوں کو 3.5 لاکھ پودے
مفت تقسیم کئے گئے تاکہ وہ
اپنے گھروں کے آگے پیچھے
آنگنوں میں انہیں لگا سکیں۔

ان کوششوں سے اچھے نتیجے سامنے آئے اور دہلی کے ہر علاقے
2015 میں 299.77 اسکوئر کلومیٹر سے بڑھ کر 2017 میں
305.41 اسکوئر کلومیٹر ہو گیا ہے۔ اگلے سال سرکار آرڈر بلو اے مار
کیٹ ایسوسی ایشن اور این جی او کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر دہلی میں
لاکھوں اور پودے لگانے کی تیاری میں ہیں اس کے لئے ایگزیکٹو
کا استعمال کیا جائے گا۔ سینٹرل رج ایئر یا میں ولایتی کیکر کی جگہ پر نئے
پودے لگانے کی ایک طویل مدتی اسکیم شروع کر دی گئی ہے۔

دہلی کو ہر ابھرا بنائے رکھنے کے علاوہ آلودگی سے لڑنے کیلئے کئی نئی حوصلہ
افزائی اسکیمس بھی سرکار نے تیار کی ہیں سرکار صنعتی علاقوں میں کام کرنے
والے انڈسٹریل نیٹس کو آلودگی پھیلانے والے ایندھن استعمال کرنے کی
جگہ پائپڈ نیچرل گیس کا استعمال کیلئے حوصلہ افزائی کرے گی اس کیلئے
ایک لاکھ روپے تک کی امدادی رقم سرکار کی جانب سے دی جائے گی۔
اسی طرح دہلی کے ریسٹورینٹ کو بھی کوئلہ تندر کی جگہ الیکٹرک یا گیس
تندر کے استعمال کو حوصلہ افزائی دینے کیلئے 5000 روپے فی تندر
تک کی امدادی رقم سرکار کی جانب سے دی جائے گی۔ ساتھ ہی دس کے
وی اے یا اس سے زیادہ صلاحیت کے ڈیٹل جرنیٹر استعمال کرنے
والے کاروباریوں کو بھی صاف ایندھن پر منحصر الیکٹرک جرنیٹر استعمال
کرنے کیلئے حوصلہ افزائی کیا جائے گا۔

شخص آمدنی 18 - 2017 کے دوران قومی درجے کی
1,12,764 روپے کی فی شخص اوسط آمدنی سے قریب 2.92 گنا زیادہ
ہے۔

گرین بجٹ

وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ان کی سرکار نے پہلا بجٹ پیش کیا تھا تو اسے تعلیم
، صحت بجٹ کا نام دیا تھا۔ پچھلے سال پیش بجٹ میں تعلیم اور صحت کے
ساتھ ساتھ بجٹ آؤٹ کم یعنی عوام کے ٹیکس کے پیسے کو خرچ کر کے اس
سے ملنے والے آؤٹ کم پر زور دیتے ہوئے اسے آؤٹ کم بجٹ کہا گیا
اس سال بجٹ میں گرین بجٹ کے نام سے ایک اور ضروری حصہ جوڑا
جا رہا ہے۔

وزیر خزانہ نے کہا کہ دہلی سرکار نے سسٹم نیبل ڈیولپمنٹ پر کام کر رہے
گلوبل ٹینک ٹینک "ورلڈ ریسورس انسٹی ٹیوٹ" کے ساتھ تعامل کر کے
یہ سمجھنے کی کوشش بھی کی کہ مالی سال 2018-19 کیلئے دہلی سرکار نے
گرین بجٹ تجویزوں کا دہلی میں آلودگی پر کیا اثر پڑے گا۔ اس سے
دہلی میں آلودگی کے اخراج میں کافی کمی دیکھنے کو ملے گی۔

جناب سسودیا کے مطابق مالی سال 2018-19 میں دہلی ملک کا پہلا
ایسا صوبہ بنے گا جہاں آلودگی کرنے والے عناصروں کا رینل ٹائم ڈیٹا
پورے سال اکٹھا کیا جائے گا اور ان کی وجوہات کا مسلسل مطالعہ کیا جائے
گا۔ یہ کام واشنگٹن یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ
پوری دہلی میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کی فہرست بنانے کا کام بھی
پہلی بار شروع ہو گا یہ کام دنیا کے سب سے بڑے شہروں کے گروپ سی
40- سیٹیور فور کا بمیٹ لیڈر شپ کے ساتھ مل کر شروع کیا جائے گا۔

گرین بجٹ سے متعلقہ محکمہ وار

اسکیمیں

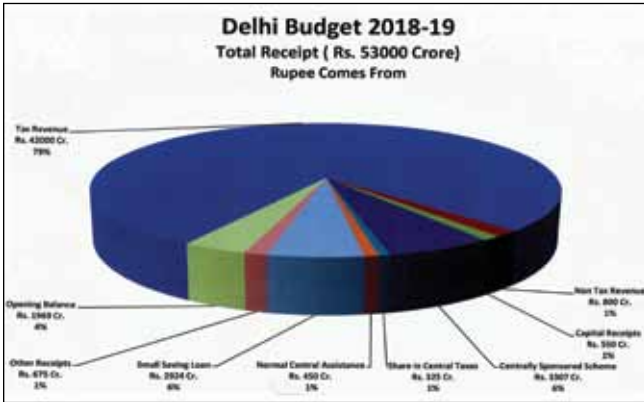
محکمہ ما حویلیات

دہلی میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں پودا لگانے کی جانب میں سرکار پچھلے
تین سال سے مشن موڈ میں کام کر رہی ہے اس سال دسمبر 2017 تک
5.5 لاکھ پودے پہلے ہی لگائے جا چکے تھے مارچ 2018 تک 3 لاکھ
اور پودے لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ ڈیوائیڈڈ اور سڑک کے کنارے پر
سول انجینیئروں کی طرف سے 7.93 لاکھ چھوٹے پیٹ پودے لگائے گئے۔



اقتصادی نقطہ نظر

جناب سودیا نے کہا ہے کہ دہلی کی مالی نظام مستقل ترقی کے صحیح راستے پر آگے بڑھ رہی ہے دہلی کا مجموعی ریاستی گھریلو مصنوعات موجودہ قیمتوں پر آئندہ اندازوں کی مطابق 2017-18 میں بڑھ کر 6,86,017 کروڑ روپے پر پہنچ جائیگا امکان ہے جو 2016-17 میں 6,16,826 کروڑ روپے تھا۔ اس طرح اس میں 11.22 فیصدی کی اضافے کا تخمینہ ہے۔ فکسڈ قیمت پر اصل مقابل میں دہلی کے جی ایس ڈی پی کی اضافی در 2017-18 میں 8.14 فیصدی رہنے کا امکان ہے۔ جبکہ قومی درجے پر یہ در 6.6 فیصدی ہے۔ دہلی کے مجموعی ریاستی گھریلو مصنوعات میں اصل سالانہ اوسط بڑھوتری 2015-16 سے 2017-18 کی مدت میں 9.1 فیصدی رہی ہے جبکہ اسی مدت کے دوران قومی درجے پر جی ڈی پی میں بڑھوتری 7.3 فیصدی رہنے کا اندازہ ہے۔ قومی درجے پر جی ڈی پی میں دہلی کا تعاون 2011-12 کے 3.94 فیصدی سے بڑھ کر 2017-18 میں 4.10 فیصدی ہو گیا۔

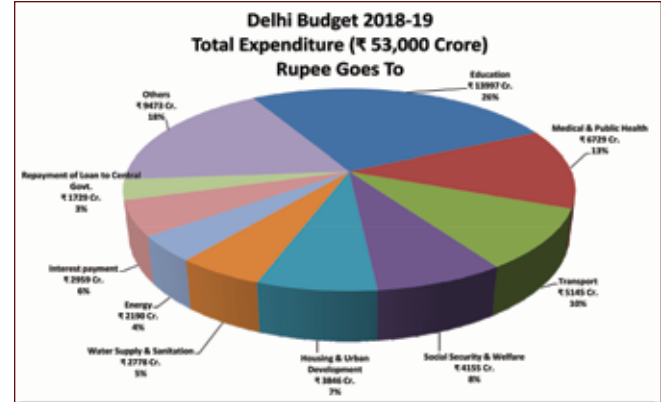


یہ حصولیابی اس کے باوجود ملی ہوئی ہے کہ ملک کی کل آبادی میں دہلی کی حصہ داری صرف 1.4 فیصدی ہے۔ دہلی کی معیشت میں خدمت کے شعبہ کی اہمیت ہے جس کی حصہ داری گروس اسٹیٹ ویلیو ایڈیشن میں 85.92 فیصدی ہے اس کے بعد 12.04 فیصدی حصہ داری درمیانی شعبہ کا اور 2.04 فیصدی حصہ داری پرائمری شعبہ کا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ دہلی کی فی شخص سالانہ اوسط آمدنی موجودہ قیمتوں پر 2017-18 میں بڑھ کر 3,29,093 روپے ہو گئی جو 2016-17 میں 3,00,793 روپے تھی اس طرح 2017-18 میں دہلی کی فی شخص سالانہ اوسط آمدنی میں 9.41 فیصدی کا اضافہ ہوا جو ایک اچھا اشارہ ہے۔ قومی اوسط سے موازنہ کریں تو دہلی کی فی

جناب سودیا نے کہا کہ تین سال پہلے ان کی سرکار نے اپنے پہلے بجٹ میں ایجوکیشن کا بجٹ

لگ بھگ دو گنا اور صحت کا بجٹ ڈیڑھ گنا کیا تھا۔ پچھلے تین سال سے لگاتار سالانہ بجٹ کا قریب ایک چوتھائی حصہ ایجوکیشن پر خرچ کیا جا رہا ہے جو نہ صرف ملک میں سب سے زیادہ ہے بلکہ سارے صوبوں کے اوسط تعلیم خرچ کا 15.6 فیصد سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح عام آدمی کو بہترین محلہ کلینک، پولی کلینک اور عوامی مفید صحت اسکیموں کے ذریعہ سے بہترین علاج حاصل کرا کر یہ طے کیا جا رہا ہے کہ دہلی کے عام خاندان کی محنت کی کمائی موٹے موٹے میڈیکل بلس پر نہ خرچ ہوں۔ پچھلے تین سال میں دہلی سرکار صحت پر اپنے سالانہ بجٹ 11.36 فیصدی خرچ کر رہی ہے جب کہ سارے صوبوں کا کل اوسط 4.9 فیصدی تک محدود ہے۔



انہوں نے کہا کہ پچھلے تین سال سے دہلی کے شہریوں کو ملک کے کسی بھی بڑے شہر کی تقابل میں سستی بجلی مل رہی ہے۔ اسی طرح مفت پینے کا صاف پانی مہیا کرانے کی اسکیم سے نہ صرف دہلی کے شہریوں کو سیدھے اقتصادی فائدہ پہونچا ہے بلکہ 20 کلو لیٹر کی منٹھلی حد ہونے کے کارن لوگوں میں پانی بچانے کا رجحان بھی بڑھا ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں نے پانی کے جائز کنٹینر لئے ہیں۔ ان منصوبوں کی بدولت سرکار نے 400 نئی کالونیوں میں گھر گھر پینے کے پانی کا کنکیشن پہونچایا ہے۔ ٹریکل اپ اکونومی کی جانب سرکار کا سب سے بڑا قدم رہا ہے۔ کم از کم مزدوری کی حد میں اضافہ۔ پچھلے سال ہی دہلی سرکار نے کم از کم مزدوری میں 37 فیصد کی بڑھوتری کی تھی۔ ملک میں آج سب سے زیادہ کم از کم مزدوری دہلی میں ملتی ہے۔

DELHI BUDGET 2018



وزیر خزانہ نے پیش کیا 53000 کروڑ روپے کا بجٹ دہلی کو ملا "گرین بجٹ" کا آکسیجن

ہے۔ بجٹ پیش کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے کہا ہے کہ ان کی سرکار نے 'ٹریکل ڈاؤن' کی جگہ 'ٹریکل اپ' ایکونومک ماڈل کو اپنایا ہے۔ 'ٹریکل اپ' ایکونومی کا سیدھا سا مطلب ہے کہ سرکار ایسی اقتصادی نیٹیاں بنائیں جن کا سیدھا فائدہ غریب اور میڈل کلاس طبقوں کو ملے اور ان کی ایجوکیشن کا درجہ بڑھے۔ وہ صحت مند رہیں اور ان کی آمدنی بھی بڑھے۔ یہی اس سرکار کا واحد نعرہ ہے۔ پڑھا لکھا ملک، صحت مند ملک، قابل ملک!

23 مارچ کو ودھان سبھا میں 2018-19 کا بجٹ پیش کرتے ہوئے صوبہ کے وزیر خزانہ جناب منیش سسودیا نے بتایا کہ ملک میں ممکنہ پہلی بار کہیں گرین بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ کل 53000 کے اس بجٹ میں ایجوکیشن، صحت اور عوامی بھلائی کی تمام منصوبوں کے علاوہ ملک کی راجدھانی کو پولیوشن فری کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے۔ گرین بجٹ میں دہلی سرکار کے چار محکموں ماحولیات، ٹرانسپورٹ، پاور اور پی ڈبلیو ڈی سے جڑی 26 منصوبوں کو شامل کیا گیا ہے۔ جن کے ذریعہ پولیوشن کنٹرول مہم کو نئی اونچائی دینے کی ترکیب

ही मनाई। उस वक्त इस स्कूल को बनाने वाले लाला रघुवीर सिंह के घर पर होली खेली जाती थी। पहली बार जिस लड़की के साथ मैंने होली खेली, वह एक सरदारनी ही थी। नाम था कँवल। वह भी मेरे साथ ही उसी स्कूल में पढ़ती थी। बाद में वह मेरी पत्नी बनी।’

केवल रंग ही नहीं, वे उस दौर के मौसम के बारे में बताते हैं कि होली के दिनों में मौसम सबसे अधिक सुहावना होता है। परिंदे अपने घोंसले बनाने में जुटे होते हैं। फूलों पर बहार आई होती है। दिल्ली में इतने फूल कभी खिले नहीं दिखते, जितने होली के मौसम में, विशेष रूप से टेसू या पलाश अपने पूरे यौवन पर होता है। उल्लेखनीय है कि पलाश के फूलों का होली से विशेष नाता है।



दिल्ली की होली की बात हो, “मधुशाला” (सुन आयी आज मैं तो होली की भनक, होली की भनक ए जी होली की भनक) का जिक्र न हो, यह कैसे संभव है। कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी चार खंडों वाली आत्मकथा के अंतिम खंड “दशद्वार से सोपान तक” में लिखा है कि ‘अमित (अमिताभ

बच्चन के चोट लगने से घायल होने पर) के साथ पहली फरवरी को हम यहां (दिल्ली) आये थे, मार्च में होली पड़ी, बुन्देलखंड के कवि ईसुरी की फागों के अनुकरण में मैंने तेजी (बच्चन) के विनोदार्थ एक फाग लिखी—

तेजी, दूर हो गए बेटे.

चले बम्बई से हम अपना सब सामान समेटे..’

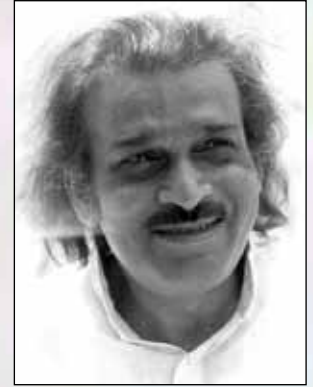


प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह “काशी के नाम” पुस्तक में अपने भाई काशीनाथ सिंह को लिखे एक पत्र (26 फरवरी 1966) में राजधानी में प्रवासियों के दुख को प्रकट करते हुए लिखते हैं कि ‘लगता है, होली में न आ सकूंगा। इसलिए इस साल की होली मेरे बगैर ही मनाओ और इजाजत दो कि

कम से कम एक साल तो दिल्ली की होली देख सकूँ। जब

यहाँ का नमक खा रहा हूँ तो यहाँ की होली में भी शरीक होना ही चाहिए।’

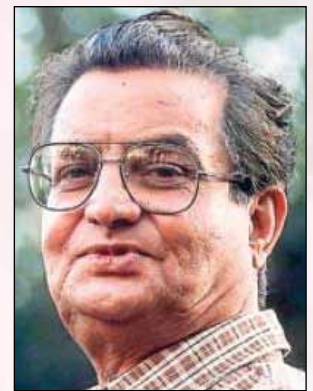
लेखक—पत्रकार सर्वेश्वरदयाल सक्सेना 70 के दशक की दिल्ली में होली पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि होली मनोरंजन का त्योहार है पर धीरे—धीरे वह इस भाव से कटता जा रहा है। यह मनोरंजन का लोकरंजन से कट जाने का ही चरम रूप है। राजधानी में दिन पर दिन रंग कम होता जा रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है।



जबकि प्रसिद्ध समाजशास्त्री पूरनचंद जोशी उसी समय के अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के दिनों के बारे में बताते हैं कि ‘उन दिनों’ वहाँ हमने सामुदायिक होली को बनाए रखा। आर्थिक विकास संस्थान में सभी प्रांतों, सभी धर्मों के लोग थे। सबके घर से मिठाइयाँ आती थीं। हमारे तब के निदेशक की पत्नी प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शीला धर पक्का गाना गाती थीं, और लोग भी गाते थे।’



प्रसिद्ध लेखक मनोहर श्याम जोशी ने 80 के दशक में दिल्ली की होली के बारे में लिखा है कि ‘जब तक दिल्ली में कुमाउँनी लोगों की बिरादरी गोल मार्केट से लेकर सरोजिनी नगर तक के सरकारी क्वार्टरों में सीमित थी, वे अपनी होली परंपरागत ढंग से मना पाते थे, अब नहीं। जबकि रघुवीर सहाय ने पुस्तक “लेखक के चारों ओर” में लिखा है कि ‘हर बड़े शहर में ऐसे लोग हैं—राजधानी (दिल्ली) में तो बहुत हैं। ये लोग न तो यह जानते हैं कि वे होली क्यों नहीं खेलना चाहते न यह समझते हैं कि उन्हें होली क्यों खेलनी चाहिए।’



नलिन चौहान ■



दिल्ली सरकार

आप की सरकार

तीन साल में
हुआ कमाल



सरकार ईमानदार हो तो
सब कुछ हो सकता है